शनिवार, 18 अप्रैल, 2026

बैशाख, शु.प., प्रतिपदा विक्रमीय संवत् 2083

मूल्य Rs. 4, (कोलकाता Rs. 3)

वर्ष : 21, संख्या : 135, पृष्ठ-8

कोलकाता

RNI No. WBHIN/2005/16483

www.bharatmitranews.com

भारतमित्र

प्रथम प्रकाशन 1878

ममता के करीबी तृणमूल नेता के घर पर आयकर छापा

पेज-3

प्रधानमंत्री मोदी ने हरिवंश को तीसरी बार उपसभापति बनने पर दी बधाई

पेज-5

जामुड़िया फैक्ट्री में हादसा, श्रमिक की मौत पर भड़के लोग

पेज-6

वीर चोटरानी हैम्बर्ग स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

पेज-8

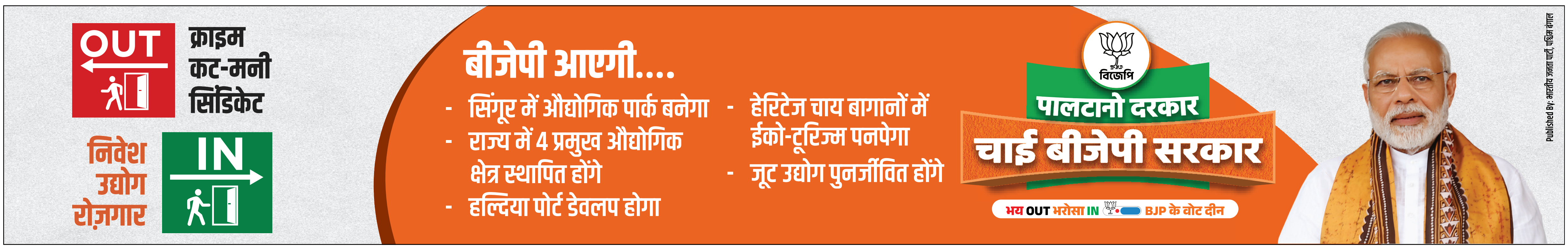

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में गिरा

नई दिल्ली, एजेंसी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सदन में %संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026%, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। मतदान के समय सदन में कुल 528 सांसद मौजूद थे। विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी।

इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान पर आक्रमण था और इसे हमने हरा दिया है तो यह अच्छी बात है। संसद परिसर में बातचीत के दौरान पत्रकारों ने पूछा कि आपने एपस्टीन की चर्चा की, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री का चेहरा देखा?

दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी

लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। सरकार ने इस विधेयक के साथ %परिसीमन विधेयक, 2026% और %संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026% को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

दो विधेयकों पर क्यों नहीं हुई वोटिंग

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संविधान संशोधन(131वां संशोधन) बिल पास नहीं हुआ, सदन में वोटिंग के दौरान इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों %परिसीमन विधेयक, 2026% और %संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026% को आगे नहीं बढ़ा सकते।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान पर आक्रमण था और इसे हमने हरा दिया है तो यह अच्छी बात है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह महिला बिल नहीं है, यह हिंदूस्तान का जो राजनीतिक ढांचा है, चुनावी ढांचा है, उसे बदलने की कोशिश है। यह हमने रोक दिया है। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आप महिला आरक्षण चाहते हैं तो 2023 का महिला आरक्षण बिल निकालिए, उसका क्रियान्वयन आज से करिए और पूरा विपक्ष 100 फीसदी आपको समर्थन देगा और महिला आरक्षण को हम तत्काल लागू कराएंगे।

ये लोकतंत्र की बात थी: प्रियंका गांधी

वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, महिला आरक्षण की बात नहीं थी ये लोकतंत्र की बात थी, देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप महिला आरक्षण को इस तरह परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। ये मुमकिन नहीं था कि ये बिल पारित हो। देश के लोकतंत्र के लिए, देश की अखंडता के लिए ये बड़ी जीत है।

सदन में वोटिंग के नतीजे

पक्ष 298

विपक्ष 230

कुल संख्या 528

दोहरी नागरिकता मामले में फंसे राहुल गांधी

लखनऊ, एजेंसी कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी की शुक्रवार को दोहरी नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राहुल के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए।

शासकीय अधिवक्ता वी के सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि या तो वह इस मामले की जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाएं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया।

राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता रखने का आरोप है। इसके खिलाफ एस विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और दावा किया था कि राहुल के पास दो देशों के पासपोर्ट हो सकते हैं, जो कि भारतीय कानून का उल्लंघन है। इसी को लेकर लंबे समय से हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।

ब्रिटिश नागरिकता की होगी सीबीआई जांच

क्या है मामला

लखनऊ की विशेष एम पी / एम एल ए अदालत ने 28 जनवरी को, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ शिशिर हाईकोर्ट पहुंचे थे। एम पी / एम एल ए अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इस मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग की है। याची ने बीएनएस, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। इस मामले की पहले सुनवाई करते हुए, पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि राहुल की ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ मिली शिकायत पर उसने क्या कार्रवाई की है। साथ ही केंद्र से मामले संबंधी रिकार्ड भी तलब किए थे।

एफआईआर की मांग

राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में दायर याचिका में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के मामले बनते हैं।

तृणमूल ने रची घुसपैठियों को मतदाता बनाने की साजिश : देवेंद्र फडणवीस

कोलकाता, (हि.स.)। तृणमूल कांग्रेस पर घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम उचित कारणों से हटाए गए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस लगातार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध कर रही है। शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वह कानूनी उपाय अपनाकर अपील कर सकता है। जिन लोगों के नाम सही कारणों से हटाए गए, उन्होंने विरोध नहीं किया। केवल तृणमूल कांग्रेस को ही आपत्ति क्यों है? उच्चतम न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां अवश्य कीं, लेकिन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई।

ईडी व आयकर का देवाशीष कुमार के ठिकानों पर छापा

कोलकाता, (हि. स.)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक रियल एस्टेट कंपनी और एक निर्माण संस्था के ठिकानों पर छापेमारी की वहीं आयकर विभाग की तरफ से रासबिहारी के तृणमूल उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई। शुक्रवार सुबह सीजीओ कॉम्प्लेक्स से ईडी की कई टीमें पहुंचीं। उनके साथ केंद्रीय बल भी थे। ईडी की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह से ही एक रियल एस्टेट कंपनी के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ईडी के अधिकारी साल्ट लेक और कोलकाता में चार जगहों पर पहुंचे हैं। उन्होंने न केवल रियल एस्टेट कंपनी, बल्कि एक अन्य निर्माण कंपनी के कार्यालय पर भी छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, ये सर्च ऑपरेशन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले को लेकर है। गौरतलब है कि, कुछ दिन पहले इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े घरों, फ्लैटों और दफ्तरों में तलाशी अभियान चलाया गया था। ईडी ने दावा किया कि यह ऑपरेशन चुनाव से पहले अवैध वित्तीय लेनदेन को रोकने और कुछ भूमि संबंधी मामलों में लेनदेन की जानकारी खोजने के लिए था। दूसरी ओर, ईडी के अलावा एक अन्य केंद्रीय एजेंसी आयकर विभाग भी कोलकाता में तलाशी अभियान चला रही है। उन्होंने शुक्रवार सुबह रासबिहारी निर्वाचन क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर सहित कई स्थानों पर दबिश दी। आयकर विभाग की एक टीम शुक्रवार सुबह रासबिहारी के निवर्तमान विधायक देबाशीष के मनोहरपुकुर रोड स्थित घर पहुंची। न सिर्फ उनके घर बल्कि मनोहरपुकुर रोड स्थित उनके चुनाव कार्यालय पर भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा था। इसके अलावा देवाशीष का मोतीलाल नेहरू रोड स्थित ऑफिस में भी तलाशी अभियान चलाया गया। उधर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल चुनाव से पहले दो केंद्रीय एजेंसियों के दोहरे तलाशी अभियान पर सवाल उठा रही है।

एजेंसी की कार्रवाई पर बिफरीं ममता

कूचबिहार, (हि.स.) कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेता और पार्टी उम्मीदवार देवाशीष कुमार के घर और कार्यालय पर आय कर की छापेमारी को लेकर पार्टी सुप्रीमों ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे लेकर उन्होंने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कूचबिहार के रासमेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सीधी राजनीतिक लड़ाई में विफल हो चुकी है, इसलिए तृणमूल उम्मीदवारों और पार्टी कार्यालयों पर प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग के जरिए छापेमारी कराई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि काले धन के हवाला कारोबार करने वाले लोग बंगाल में बैठे हैं, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही। इसके बजाय मेरे उम्मीदवार के घर और पार्टी कार्यालय में तलाशी ली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके विमान की भी तलाशी लेने की कोशिश की गई थी और उनके सुरक्षा कर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आमने-सामने राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता मतदान पेटी के माध्यम से इसका जवाब देगी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार सुबह से रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार देवाशीष कुमार के मनोहरपुकुर स्थित आवास और कार्यालय में आयकर विभाग ने तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के साथ केंद्रीय बल के जवान भी मौजूद थे। बताया गया है कि एक साथ उनके दो ठिकानों पर जांच की गई, जिसके बाद उनके ससुराल में भी तलाशी ली गई। इस कार्रवाई को लेकर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी देखी गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है।

लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

ईरानी विदेश मंत्री ने होर्मुज पूरी तरह खोलने का किया ऐलान

तेहरान, एजेंसियां- ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ऐलान किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। हालांकि, यह जलडमरूमध्य इजरायल-लेबनान संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए ही खोला गया है, जो गुरुवार से अगले 10 दिनों तक के लिए प्रभावी है। ऐसे में फारस की खाड़ी में फंसे जहाज अब होर्मुज को पार कर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। इन जहाजों पर करीब 20000 कर्मी भी सवार हैं, जो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हवाई हमलों के बाद फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक्स पर लिखा, लेबनान में संघर्ष विराम के अनुरूप, होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी वाणिज्यिक जहाजों के गुजरने का मार्ग, संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए, पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। यह मार्ग उसी समन्वित मार्ग पर स्थित है जिसकी घोषणा इस्लामिक गणराज्य ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

कितने जहाज फंसे थे?

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से लगभग 800 जहाज फंस गए थे। इसमें लगभग 187 से अधिक ऑयल टैंकर शामिल हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इन जहाजों पर सवार कर्मियों ने पिछले एक महीने से ज्यादा समय से जमीन नहीं देखा है। हालांकि अब ईरान के ऐलान के बाद इन जहाजों के तेजी से होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने की उम्मीद है।लेबनान में संघर्ष विराम के अनुरूप, होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी वाणिज्यिक जहाजों के गुजरने का मार्ग, संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए, पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है।

इजरायल-लेबनान सीजफायर के बाद खुला होर्मुज

ईरान ने पहले ही शर्त रखी थी कि वह लेबनान में सीजफायर के बिना होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलने वाला है। इस कारण अमेरिका के साथ संघर्षविराम होने के बावजूद ईरान ने सीमित मात्रा में होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही शुरू की थी। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि दोनों देश 10 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद भी दिया।

लेबनान सीजफायर के बाद फैसला

प्रथम प्रकाशन 1878
भारतमित्र

फर्जी प्रेस कार्ड बांटकर मतदाताओं को प्रभावित कर रही तृणमूल : शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी पत्रकार पहचान पत्र जारी कर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर जारी संदेश में दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक परामर्श संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) की मदद से अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी मीडिया पहचान पत्र उपलब्ध कराए हैं।

उनके अनुसार, इन लोगों को पत्रकार बनाकर मतदान केंद्रों और प्रशासनिक परिसरों में प्रवेश दिलाने की योजना बनाई गई है, ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके और चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को सुनियोजित ढंग से पत्रकारों के रूप में तैनात किया जा रहा है, जिससे वे पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा और छूट का लाभ उठाकर गैरकानूनी गतिविधियां कर सकें। भारतीय जनता पार्टी नेता ने निर्वाचन आयोग से मांग की कि राज्य में हाल में जारी सभी मीडिया पहचान पत्रों की जांच कराई जाए और केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधिकृत पत्रकारों को ही मतदान केंद्रों के आसपास जाने की अनुमति दी जाए।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया था। तृणमूल का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति भरोसा कार्ड योजना के नाम पर महिलाओं को आर्थिक सहायता का वादा करते हुए मतदान से ठीक पहले विभिन्न क्षेत्रों में प्रपत्र वितरित कर रही है। पार्टी ने इसे मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास बताते हुए निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। लिखे जाने तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से शुभेंदु अधिकारी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

देवाशीष हलदार और आसफाकुल्ला नाइया के तबादले का आदेश हाई कोर्ट ने रद्द किया

कोलकाता, । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चिकित्सक देवाशीष हलदार और आसफाकुल्ला नाइया के तबादले संबंधी राज्य स्वास्थ्य विभाग के आदेश को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति ऋतब्रत कुमार मित्र ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की यह पदस्थापन संबंधी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है और राज्य के स्वास्थ्य-शिक्षा विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया के विपरीत है। अदालत ने इसी आधार पर स्वास्थ्य विभाग का आदेश निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले चिकित्सक अनिकेत महतो के तबादले का आदेश भी न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है। पिछले

वर्ष जून महीने में जूनियर डॉक्टर देवाशीष हलदार, आसफाकुल्ला नाइया और अनिकेत महतो के तबादले को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इन चिकित्सकों से परामर्श प्रक्रिया के दौरान नियमों के अनुसार पूछा गया था कि वे किस स्थान पर नियुक्ति चाहते हैं। आरोप था कि इसके बावजूद तीनों को उनकी पसंद के स्थान पर पदस्थापना नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि आर. जी. कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टरों के एक वर्ग ने आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में अनिकेत महतो, देवाशीष हलदार और आसफाकुल्ला नाइया शामिल थे।

गैस सिलेंडर लीक होने से बिरयानी दुकान में लगी आग

सिलीगुड़ी, । सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास के पास बानेश्वर मोड़ इलाके में एक बिरयानी दुकान में शुक्रवार को गैस सिलेंडर से आग लगने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को दुकान में खाना बनाते समय अचानक गैस लीक होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से दुकान के अंदर रखे चार गैस सिलेंडरों को बाहर निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उनकी कोशिशों से आग काफी हद तक नियंत्रित कर ली गई। बाद में मौके पर दमकल की एक गाड़ी पहुंची, साथ ही आशिघर पुलिस चौकी और ट्रैफिक पुलिस के कर्मी भी मौजूद रहे।

दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। हालांकि, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दमकल की टीम करीब आधे घंटे की देरी से पहुंची, जिससे नाराजगी देखी गई।

राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान या जनहानि नहीं हुई, हालांकि दुकान में मामूली क्षति हुई है।

सीबीएसई 10वीं में डीपीएस दुर्गापुर का शानदार प्रदर्शन

दुर्गापुर । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर के छात्र-छात्राओं ने एक बार फिर अपनी मेधा का परचम लहराया है। इस वर्ष स्कूल का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जिसमें परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं।

परीक्षा परिणामों में श्रेयान मंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 500 में से 498 अंक प्राप्त किए और 99.6 प्रतिशत के साथ स्कूल में प्रथम

श्रेयान मंडल 99.6 प्रतिशत अंकों के साथ टापर

स्थान हासिल किया। वहीं अर्नब दत्ता ने 497 अंक यानी 99.4 प्रतिशत के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही श्रीजेश दास ने 496 अंक लाकर 99.2 प्रतिशत के साथ विद्यालय में तृतीय स्थान हासिल कर शानदार सफलता दर्ज की है। स्कूल से इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 207 विद्यार्थी शामिल हुए थे और सभी विद्यार्थी सफल हुए है। विद्यालय का कुल औसत परिणाम 87.73 प्रतिशत रहा है। बच्चों की इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों में भारी उत्साह है।

केंद्रीय विद्यालय दुर्गापुर सीएमईआरआई के परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहे

दुर्गापुर । दुर्गापुर शहर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दुर्गापुर सीएमईआरआई के दसवीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 2026 की परीक्षा में आशातीत सफलता हासिल की। उक्त परीक्षा में विद्यालय की ओर से 19 लड़के और 19 लड़कियां (कुल 38 छात्र छात्राएं) सम्मिलित हुए थे और सभी को सम्मानजनक परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ। 38 में 33 छात्र इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें 14 बच्चों ने विशेष योग्यता के साथ 90 से 98 फीसदी अंक हासिल किए तथा 23 छात्रों ने 75 फीसदी से ऊपर अंक हासिल करते हुए विद्यालय का मान बढ़ाया। सेमंती पाल और स्निग्धा घोष दोनों छात्राओं ने 98 फीसदी अंक प्राप्त करते हुए संयुक्त रूप से विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि 97 फीसदी एवं 96. फीसदी प्राप्तांको के साथ सैकत मोहंती और जनिका मित्रा ने क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान हासिल किए। इनमें से कुछ छात्रों ने विभिन्न विषयों में शत प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी मेधा शक्ति का लोहा मनवाया। विद्यालय का यह शत प्रतिशत परिणाम छात्रों की उपलब्धि के साथ साथ विद्यालय के प्राचार्य के कुशल मार्गदर्शन एवं क्षमता वान एवं परिश्रमी शिक्षकों के प्रयास का प्रतिफल है । विद्यालय के प्राचार्य विप्लव सरकार समेत सभी शिक्षकों ने बच्चों की इस अप्रतिम उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना व्यक्त की है।

डीवीसी केटीपीएस फेज-|| में बॉयलर यूनिट #3 के प्रथम कॉलम एरेक्शन का शुभारंभ

कोडरमा । डीवीसी केटीपीएस फेज-|| में बॉयलर यूनिट ⧣3 (एस1एल-1पी-101) के प्रथम कॉलम एरेक्शन का शुभारंभ पारंपरिक विष्वकर्मा पूजा के साथ विधिवत रूप से किया गया, जिसमें परियोजना के सफल निष्पादन हेतु भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर संजय कुमार, सीजीएम एवं एचओपी, के साथ-साथ मानस नस्कर, जीएम (फेज-द्वद्व), तपस मिर्धा, जीएम (एएमएस), एस. चट्टोपाध्याय, प्रोजेक्ट डायरेक्टर (बीएचईएल), तथा मिथुन सिंह, आरसीएम (सिमार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस कार्यक्रम में केटीपीएस फेज-द्वद्व की समर्पित टीम के सदस्य, जिनमें सूरज पटनायक, दिनेश कुमार सोनी एवं कुंदन कुमार झा शामिल हैं, ने सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग प्रदान किया। यह समारोह परियोजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सामूहिक प्रतिबद्धता, टीमवर्क एवं सफल कार्यान्वयन की सकारात्मक शुरुआत को दर्शाता है।

सत्तारूढ़ पार्टी पर चुनावी बैनर खोलने का आरोप, दुर्गापुर में तनाव

दुर्गापुर । जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में राजनीतिक तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। इस बार सत्तारूढ़ पार्टी के बैनर हटाने को लेकर शहर में तनाव फैल गया है। यह घटना एबीएल अस्पताल गेट परिसर इलाके में हुई।

सातारूढ़ पार्टी का दावा है कि उस इलाके में दुर्गापुर पूर्व से तृणमूल उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार के समर्थन में लगाए गए बैनर किसी ने रात के अंधेरे में हटा दिए। उनके आरोप राम और लेफ्ट दोनों खेमों पर हैं। उनका सवाल है कि दूसरी पार्टियों के बैनर लगे होने के बावजूद सिर्फ तृणमूल का बैनर ही क्यों हटाया गया? शुक्रवार सुबह इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तृणमूल के कार्यकर्ता और समर्थक गुस्से में आ गए। वे विरोध में सड़कों पर उतर आए और नारे लगाकर प्रदर्शन करने लगे।

प्रदीप मजूमदार ने घटना की कड़ी निंदा की और कहा, बैनर और फेस्टून फाड़कर चुनाव नहीं जीत सकते। ये सब भड़काने वाली और उत्तेजक हरकतें हैं। हमने अपने सहकर्मियों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे उकसावे के जाल में न फंसें। दूसरी ओर, दुर्गापुर पूर्व से भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बनर्जी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं तृणमूल की संस्कृति हैं, भाजपा की नहीं। भाजपा दीवारों और पोस्टरों पर कब्ज़ा करने की यह राजनीतिक नहीं करती। हम लोगों के दिलों पर कब्ज़ा करने में यकीन रखते हैं। इसीलिए आज भाजपा देश के 19 राज्यों में सत्ता में है।÷

आसनसोल-पटना-आसनसोल स्पेशल का मननपुर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव

कोलकाता, नि.सं रेलवे ने 18 अप्रैल से आसनसोल-पटना-आसनसोल स्पेशल 03201/03202 का मननपुर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। पटना-आसनसोल स्पेशल 03202 और आसनसोल-पटना स्पेशल 03201 क्रमशः 7~15 बजे और 17~21 बजे मननपुर पहुंचेंगी और दोनों दिशाओं में 1 मिनट का ठहराव करेंगी।

साड़ी डीलर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी

निर्मल सराफ पुन: अध्यक्ष मनोनीत

कोलकाता~ कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन ने 2026-28 के लिए अपनी नई कार्यकारिणी के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव की प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण रही और टीम का चयन निर्विरोध संपन्न हुआ। बैठक के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा पदाधिकारियों के नामों का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। नई टीम इस प्रकार है: अध्यक्ष- निर्मल सराफ, मंत्री संजय चोपड़ा, उपाध्यक्ष सत्यनारायण डिडवानिया, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, सह मंत्री गोपाल जैन, न्याय प्रमुख- पवन जी जाजोदिया।

कार्यकारिणी सदस्य: सर्वश्री भूपेश अग्रवाल, अजय पंसारी, अरविंद शाह, राजेश कुमार बैंगानी, रमेश कुमार जैन, विनय चोरड़िया, विकास शर्मा, सुनील कुमार शाह, सुनील बाहेती, सुमित जैन, सौरभ जैन, विजय शंकर अग्रवाल, विष्णु सराफ और गौतम अग्रवाल तथा सहायक सदस्य~ विकास अग्रवाल और राहुल अग्रवाल।

नवनियुक्त अध्यक्ष निर्मल सराफ ने विश्वास व्यक्त किया कि अनुभवी सदस्यों के मार्गदर्शन से व्यापार की नई पद्धतियों और चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना और व्यापार के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। टीम के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर व्यापारिक हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है।

तृणमूल उम्मीदवार अभिजीत घटक ने किया जन- संपर्क

बराकर । बराकर शहर के हनुमान चढ़ाई स्थित एक निजी मैरेज हॉल में तृणमूल प्रार्थी अभिजीत घटक ने एक बैठक की। बैठक में उन्होंने भगत परिवार, कुशवाहा समाज एवं बरनवाल समाज के वरिष्ठ लोगों से तृणमूल के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता राजेश कुशवाहा ने की। इस दौरान समाज के लोगों ने अभिजीत घटक का स्वागत किया। अभिजीत घटक ने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि तृणमूल हमेशा लोगों के साथ खड़ी होकर विकास करती है। इस अवसर पर पार्षद राधा सिंह, रॉबिन लायक, सजल घोष, पप्पू सिंह पटेल भगत बिंदेश्वरी भगत पिंकू सुहासरिया नन्हे भगत किशोर साव भुनेश भगत सहित अन्य लोग मौजूद थे।

कुल्टी प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने लहराया परचम

कुल्टी । प्रियदर्शिनी पब्लिक स्कूल कुल्टी के छात्र- छात्राओं ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शतप्रतिशत रिजल्ट हासिल करके पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। जिसे लेकर स्कूल के संस्थापक केके तिवारी ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी है।

इस संबंध में प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल कुल्टी के प्रिंसपल राकेश तिवारी ने दूरभाष पर बताया कि इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 77 बच्चे शामिल हुए और सभी बच्चे सफल रहे। कुल्टी पूर्वसा कालोनी की रहने वाली छात्रा श्रेया केशरी 95 प्रतिशत अंक लाकर स्कूल टापर हुई है।

शुभाशीष साव 94 . 4 प्रतिशत अंक से सकेंड तथा अंकुश सिन्हा 92. 2 प्रतिशत अंक लाकर तीसरे स्थान पर हैं।

सफा अफताब 92 . 2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर चौथे स्थान पर हैं। राकेश तिवारी ने बताया शिक्षा के क्षेत्र में कोई पीछे नहीं छूटे, इसलिए नर्सरी से कक्षा पांच तक मुफ्त एडमिशन लिया जा रहा है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चो को विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विशेष तैयारी करवाई जाती है।

एसकेएस पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा शत-प्रतिशत

दुर्गापुर 17 अप्रैल । कोयलांचल क्षेत्र रानीगंज के मंगलपुर इलाका स्थित नामी-गिरामी अंग्रेजी माध्यम के एसकेएस पब्लिक स्कूल के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 2026 की परीक्षा में आशातीत सफलता हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। उक्त परीक्षा में विद्यालय की ओर से कुल 351 छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुये थे।

जिनमे से 350 विद्यार्थियों ने आशातीत सफलता हासिल की। विद्यालय के छात्र सैकत मंडल ने 99 फीसदी अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर का स्थान हासिल किया। जबकि अंकना माजी और निकुंज केडिया ने 97.60 फीसदी अंक प्राप्त करते हुये संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

वहीं अंजान नंदी ने 97.40 फीसदी अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया। विद्यालय के संपूर्ण नतीजे पर ध्यान दिया जाय तो 22 विद्यार्थियों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल कर अपनी मेधा शक्ति का लोहा मनवाया।

इसके अलावा 63 विद्यार्थियों ने 90 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए।

प्लेटफार्म टिकट की कीमत अभी भी 10 रुपये

कोलकाता,नि.सं~ पोइला बोइशाख (बंगाली नव वर्ष) के अवसर पर, श्रीजानी (नाम बदला हुआ) हावड़ा स्टेशन जा रही थी। उसकी सहेली अर्पिता (नाम बदला हुआ) बंडेल से लोकल ट्रेन से आ रही थी। हावड़ा स्टेशन पर अर्पिता का स्वागत करने के बाद, दोनों ने विभिन्न आभूषण की दुकानों पर जाकर हालखाता में शामिल होने की योजना बनाई। उनके माता-पिता ने उन्हें विभिन्न आभूषण व्यवसायों के निमंत्रणों को स्वीकार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोनों लड़कियां इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थीं कि पूरा दिन वे स्वतंत्र रूप से दुकानों में घूमेंगी, ठंडे पेय और संदेश जैसी मिठाइयों का आनंद लेंगी और उपहार प्राप्त करेंगी। और अगर उन्हें बीच में मौका मिला, तो वे किसी शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल खाना भी चख सकते हैं।श्रीजानी हावड़ा स्टेशन पहुंची। अर्पिता की ट्रेन आने वाली थी। इधर-उधर देखने के बाद, श्रीजानी प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पर कतार में खड़ी हो गई। जब वह 50 रुपये का नोट दे रही थी, तो काउंटर पर मौजूद बुकिंग क्लर्क ने उससे 10 रुपये मांगे क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत सिर्फ 10 रुपये थी। हैरान होकर श्रीजानी ने पूछा, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ी नहीं है? जवाब आया, नहीं महोदया, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपये काफी समय से है।

कुल्टी में बीएलओ ने शुरू किया बूथ स्लिप वितरण

कुल्टी । आगामी विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए %बूथ लेवल ऑफिसर% द्वारा घर-घर जाकर बूथ स्लिप बांटने का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र के बीएलओ साबिर मास्टर ने बूथ संख्या 23 के तहत आने वाले क्षेत्रों में इस अभियान का आगाज़ किया। इसी क्रम में उन्होंने भाजपा जिला मीडिया इंचार्ज व कुल्टी विधानसभा उपाध्यक्ष टिंकू वर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की और बूथ स्लिप वितरण की प्रक्रिया को साझा किया। इस अवसर पर टिंकू वर्मा ने चुनाव आयोग की इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा, आयोग का यह कदम सराहनीय है।

घर बैठे बूथ स्लिप मिलने से मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने में सुविधा होगी और वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

डीएसटीपीएस में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस का आयोजन

दुर्गापुर 15 अप्रैल । डीवीसी डीएसटीपीएस अंडाल में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया, जिसके साथ ही विभिन्न जागरूकता एवं सुरक्षा-उन्मुख गतिविधियों के

अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ

साथ अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष की थीम- सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा जागरूक समाज ङ्क अग्नि रोकथाम के लिए साथ मिलकर, ÷सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज ङ्क अग्नि निवारण के लिए एकजुट है, जो विद्यालयों, अस्पतालों एवं समाज में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाती है।

कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से अनिल कुमार जैन (मुख्य महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रमुख), सुखदेव खान (वरिष्ठ महाप्रबंधक, ओ एंड एम), राजेश कुमार लायक (महाप्रबंधक, एएमएस), किशन मंडल (उप महाप्रबंधक, स्वास्थ्य सेवाएं), संदीप कर्मकार (उप महाप्रबंधक, सुरक्षा), सुखेंदु मंडल (सेफ्टी ऑफिसर) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त सीआईएसएफ डीएसटीपीएस इकाई के सहायक कमांडेंट सहित अन्य सीआईएसएफ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई।

शुरुआत में बलिदानी अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

अनिल कुमार जैन ने कहा कि अग्नि सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए निरंतर सतर्कता, प्रशिक्षण तथा सुरक्षा मानकों के पालन की आवश्यकता है।

सुप्रभात

18 अप्रैल 2026, शनिवार, वर्ष मन्मथ (2083) बैशाख, शु .प., प्रतिपदा, सूर्योदय 06 :17 ,सूर्यास्त 17. 23

आज का राशिफल

मेष आज किस्मत आपको एक बड़ा संकेत दे रही है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अटका काम अचानक सुलझ सकता है।

तुला सुबह की शुरुआत ही खुशखबरी लेकर आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ आज का दिन आपके लिए मौके लेकर आया है। कोई नई खरीदारी दिल खुश कर देगी।

वृश्चिक धैर्य ही आपकी असली ताकत है। मीठी वाणी से आप हर मुश्किल आसान कर सकते हैं।

मिथुन भागदौड़ भरा दिन है, लेकिन राहत की बात कि मदद खुद चलकर आएगी।

धनु आज रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है। जीवनसाथी से कुछ भी छुपाना भारी पड़ सकता है।

कर्क आज का दिन परीक्षा ले सकता है, लेकिन आप संभाल लेंगे। काम में फोकस बढ़ेगा।

मकर आज नौकरी वालों के लिए खुशखबरी है। नया पद या प्रमोशन मिल सकता है।

सिंह आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है, मन में चल रही उलझनें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं।

कुंभ आज का दिन आपको मुस्कुराने की वजह देगा। समस्याओं का हल मिलेगा।

कन्या सेहत पर भी लापरवाही मत कीजिए। पेट से जुड़ी परेशानी आपको परेशान कर सकती है।

मीन आज थोड़ा संभलकर चलना होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए कंट्रोल जरूरी है।

ममता के करीबी तृणमूल नेता के घर आयकर छापा

अवैध जमीन कब्जा मामले में उछला तृणमूल नेता का नाम

कोलकाता, (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अवैध जमीन कब्जा और धन शोधन मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। शुक्रवार को आयकर विभाग की एक टीम ने केंद्रीय सशस्त्र बलों की भारी सुरक्षा में तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता कुमार साहा के कालीघाट स्थित आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू किया। यह इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आधिकारिक आवास के निकट है।

कुमार साहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई उसी मामले से जुड़ी है जिसमें आयकर विभाग की दूसरी टीम तृणमूल कांग्रेस विधायक और नगर निगम के मेयर परिषद के सदस्य देवाशीष कुमार के आवास तथा चुनावी कार्यालय में भी तलाशी ले रही है। इसी प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने भी कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में एक रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तरों तथा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता कुमार साहा और देवाशीष कुमार के आवास के बाहर जुट गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कुमार साहा किसी निर्वाचित पद पर नहीं हैं, लेकिन उन्हें तृणमूल कांग्रेस का प्रभावशाली संगठनकर्ता माना जाता है। व्यवसायी पृष्ठभूमि वाले साहा को कोलकाता में पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी संभालने वाला नेता माना जाता है।

वहीं, देवाशीष कुमार को उनके पारंपरिक रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस गिरोह ने फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार कर सार्वजनिक जमीन समेत कई भूखंडों पर अवैध कब्जा किया और बाद में उन जमीनों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए बड़े रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू कीं। इस मामले में एक अप्रैल को बेहाला क्षेत्र में कंपनी के एक अधिकारी के घर से एक करोड़ रुपये से अधिक नकद बरामद किया गया था। इसके अलावा कसबा इलाके में एक व्यवसायी के घर से बिना लाइसेंस के हथियार भी मिले थे।

नंदीग्राम में चुनावी तनाव, भाजपा नेता ने सुफियान पर दर्ज कराई शिकायत

पूर्व मेदिनीपुर, (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम एक बार फिर राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है। तृणमूल कांग्रेस नेता शेख सुफियान पर भाजपा के एक नेता को धमकी देने और अपशब्द कहने का आरोप लगा है। इस मामले में नंदीग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक तनातनी तेज हो गई है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नंदीग्राम में राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है।

वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। इस बार भी यह सीट बेहद अहम मानी जा रही है।

आगामी चुनाव में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के सामने उनके पूर्व करीबी सहयोगी रहे पवित्र कर को तृणमूल कांग्रेस ने मैदान में उतारा है।

इसी बीच इलाके में बमबाजी के आरोपों के कारण माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। भाजपा के तमलुक संगठनात्मक जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव अब्बास बेग ने आरोप लगाया है कि 15 अप्रैल को नंदीग्राम के दाउदपुर ग्राम पंचायत के नयनान इलाके में पवित्र कर के समर्थन में एक पथसभा आयोजित की गई थी। उसी दौरान तृणमूल नेता शेख सुफियान ने उन्हें लक्ष्य कर गाली-गलौज की और धमकी दी। अब्बास बेग ने नंदीग्राम थाने में इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई है।

उनका यह भी आरोप है कि 16 अप्रैल की रात दाउदपुर स्थित उनके घर के पास बमबाजी की गई। सूचना मिलने पर नंदीग्राम थाने के आईसी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इलाके से एक ताजा बम बरामद किया।

हुमायूं कबीर ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

कोलकाता, (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर के कथित स्टिंग वीडियो को लेकर राज्य की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। अब इस वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ में मामला दायर किया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनकी छवि खराब करने के लिए साजिश के तहत यह वीडियो तैयार कर प्रसारित किया गया। उन्होंने अदालत से मामले की जांच के निर्देश देने की मांग की है। इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि नौ अप्रैल को हुमायूं कबीर का एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आया था। वीडियो में उन्हें किसी भाजपा नेता से बातचीत करते हुए सुना गया। कथित बातचीत में हुमायूं कबीर यह कहते सुनाई देते हैं कि वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। वीडियो में यह भी दावा किया गया कि उनकी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से बातचीत हुई है और उन्हें दिल्ली ले जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मिलाने की बात कही गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से संपर्क होने का भी उल्लेख किया गया। कथित वीडियो में हुमायूं कबीर को यह कहते हुए भी सुना गया कि यदि मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी से दूर होते हैं, तो हिंदू मतदाता स्वतः भाजपा की ओर चले जाएंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।

मछली पर राजनीति नहीं, मछुआरों का विकास जरूरी : दिलीप घोष

खड्गपुर, (हि. स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में मछली के विषय पर हो रही राजनीति को अनावश्यक बताते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह जनता के बीच यह भ्रम फैलाकर भय का वातावरण निर्मित कर रही हैं कि भाजपा के सत्ता में आने पर बंगालियों के खान-पान पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उन्हें मछली खाने से वंचित कर दिया जाएगा। शुक्रवार को चुनावी अभियान के क्रम में दिलीप घोष ने आईआईटी खड्गपुर स्थित मछली मंडी का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय विक्रेताओं और मछुआरों से भेंट कर उनसे विस्तृत संवाद किया। घोष ने स्पष्ट किया कि मछली बंगाल की सभ्यता, संस्कृति और आहार का अभिन्न अंग है, अतः इसे लेकर भ्रामक प्रचार करना सर्वथा अनुचित और तर्कहीन है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे संवेदनशील विषयों का सहारा ले रही है। उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग डेढ़ दशक से सत्तासीन होने के उपरांत भी वर्तमान शासन मछुआरों के कल्याण हेतु कोई ठोस और दूरगामी नीति बनाने में विफल रहा है।

आज भी राज्य के मत्स्य जीवी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आधुनिक आधारभूत संरचना, शीत भंडारण की अनुपलब्धता और सुदृढ़ विपणन व्यवस्था के अभाव में प्रदेश का मत्स्य उद्योग अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित नहीं हो पाया है। यही कारण है कि बंगाल को अपनी स्थानीय मांग की पूर्ति हेतु विवश होकर आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से मछली और मछली के बीज मंगाने पड़ते हैं। दिलीप घोष ने बल देते हुए कहा कि बंगाल के मछुआरे अत्यंत परिश्रमी हैं, किंतु उन्हें सही प्रोत्साहन और सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है।

उन्होंने आह्वान किया कि मछली पर तुच्छ राजनीति करने के स्थान पर इस उद्योग को सशक्त बनाने और मछुआरों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने हेतु गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के पश्चात बनने वाली नई सरकार मछुआरों के हितों को प्राथमिकता देगी और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु बेहतर कदम उठाएगी।

सबंग में महिला से दुर्व्यवहार को लेकर अभिषेक बनर्जी ने दी चेतावनी

कोलकाता, (हि.स.)। पश्चिम मिदनापुर जिले के सबंग में चुनाव प्रचार के दौरान हरिजन पल्ली में एक महिला और उसकी छोटी बच्ची के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास सभी के नाम मौजूद हैं और चार तारीख के बाद सभी को पीड़ित महिला तथा उसकी दो वर्ष की बच्ची के सामने माफी मांगनी होगी। जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात सबंग विधानसभा क्षेत्र के हरिजन पल्ली इलाके में स्थानीय गृहिणी साथी घोराई कुइला की छोटी बच्ची से कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर गलती से फट गया। आरोप है कि इसके बाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता महिला के घर पहुंच गए। बच्ची के सामने ही महिला को धमकाया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। इस मामले में सबंग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के विरोध में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी की ओर से शिकायत दी गई है। आठ आरोपितों में से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने जिला प्रशासन पर भरोसा जताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद व्यक्त की।

अभिषेक ने यह भी आरोप लगाया कि वामपंथी दल से जुड़े कुछ असामाजिक तत्व अब दल बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इलाके की शांति व्यवस्था बिगाडने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

राजस्थान के सीएम भजनलाल ने सिलीगुड़ी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो

सिलीगुड़ी, (हि. स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार शंकर घोष के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को रोड शो किया।

इस रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे मार्ग पर पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली और माहौल में जबरदस्त उत्साह और जोश नजर आया। रोड शो के दौरान समर्थक पार्टी के झंडे और बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। इससे इलाके में चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैंने बंगाल का जो माहौल देखा है, उससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि भाजपाइस बार बंगाल में सत्ता में आने वाली है। राज्य की जनता बदलाव चाहती है। चुनाव से पहले इस तरह के बड़े रोड शो को भाजपा की ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

कोलकाता के कस्बा विधानसभा सीट से सीपीआईएम की प्रत्याशी दीपू दास का तिलजला इलाके में जारी जन संपर्क अभियान फोटो- भारतमित्र

चोपड़ा में भाजपा एवं तृणमूल के बीच झड़प, फायरिंग का आरोप

उत्तर दिनाजपुर, (हि. स.)। जिले के चोपड़ा थानांतर्गत माजियाली ग्राम पंचायत के सुईगाच इलाके में गुरुवार देर रात भाजपा एवं तृणमूल के बीच हुई झड़प में फायरिंग के आरोप लगे हैं। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुक्रवार को भाजपा उम्मीदवार शंकर अधिकारी का दावा करते हुए कहा कि उस दिन चुनाव प्रचार के बाद जब वे सुईगाच इलाके से घर लौट रहे थे, उसी समय बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि उनकी कार में तोडफ़ोड़ की गई। हालांकि, तृणमूल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि जब कुछ तृणमूल कार्यकर्ता सडक़ पर खड़े होकर बात कर रहे थे, उसी समय भाजपा उम्मीदवार व उनके समर्थकों ने पहले उन्हें धमकाया और फायरिंग कर दी। तृणमूल का दावा है कि यह घटना केंद्रीय बलों के सामने हुई। फिलहाल, घटना किस वजह से हुई इसकी जांच पुलिस कर रही है।

रोजगार, 15 लाख और काले धन को लेकर ममता ने पीएम मोदी पर बोला हमला

कूचबिहार, (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कूचबिहार के रासमेला मैदान में आयोजित जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत बयानी के आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि जब तक आप यहां हैं, कृपया झूठ कम बोलिए। साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लोकतंत्र के माध्यम से आपसे तीन सवाल पूछ रही हूं।

उन्होंने पहला सवाल किया कि सत्ता में आने से पहले आपने हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज 12 वर्ष बीत गए, कितनों को नौकरी मिली? उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे में एक गैंगमैन तक नहीं है। रेलवे, विमानन तथा जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। दूसरा सवाल किया कि चुनाव से पहले हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तीसरे सवाल किया कि नोटबंदी कर काला धन वापस लाने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुत राष्ट्रीय नागरिक पंजी कर लिया गया, पहले अपनी सरकार संभालिए। कूचबिहार के राजवंशी समुदाय के लोगों को असम से राष्ट्रीय नागरिक पंजी के नोटिस भेजे गए हैं। अब कहा जा रहा है कि चुनाव के लिए बाहर से लोगों को ट्रेन से लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों की मदद से बाहरी लोगों को राज्य में प्रवेश दिलाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी बाहर से लोगों को लाकर मतदान कराया गया और अब पश्चिम बंगाल में भी ऐसी कोशिश हो रही है।

हाई कोर्ट ने रद्द की कॉलेज शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी बनाने की अधिसूचना

कोलकाता, (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों तथा शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने संबंधी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना रद्द कर दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने आयोग की ओर से संतोषजनक कारण नहीं बताए जाने पर यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने कहा कि सहायक प्राध्यापकों के वेतनमान और पद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें चुनावी दायित्व सौंपा जा सकता है। अदालत ने कहा कि आखिर किस कारण से सहायक प्राध्यापकों को मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है, इस संबंध में आयोग से बार-बार स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन आयोग उचित जवाब देने में असफल रहा। अदालत ने इसी आधार पर आयोग की अधिसूचना निरस्त कर दी। यह याचिका कॉलेज शिक्षिका रूपा बंद्योपाध्याय की ओर से दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कहा गया था कि वर्ष 2010 की निर्देशिका के स्थान पर वर्ष 2023 में नई निर्देशिका जारी की गई है। निर्वाचन कानून की धारा 26 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों को चुनाव कार्य में नियुक्त कर सकते हैं। इस दलील पर न्यायमूर्ति राव ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि ऐसा है तो इसी धारा के तहत न्यायाधीशों और न्यायमूर्तियों को भी चुनाव ड्यूटी पर लगा दीजिए। यह मजाक का विषय नहीं है। हर बार आयोग अपनी निर्देशिका बदल रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं कर रहा। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि कॉलेज शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी के कार्य से मुक्त रखा जाए और केंद्र या राज्य सरकार के आरक्षित कर्मचारियों को इस जिम्मेदारी में लगाया जाए। वहीं आयोग ने दलील दी कि मतदान में अब कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे समय अदालत के हस्तक्षेप से समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया।

हाथ में पिस्तौल लिए तस्वीर वायरल होने पर भाजपा उम्मीदवार ने कहा–

एआई क्रियेटेड तस्वीर के जरिए छवि खराब करने की साजिश

हुगली, 17 अप्रैल (हि. स.)। जिले के सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्वराज घोष की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तस्वीर में उन्हें कुर्सी पर बैठे हुए हाथ में पिस्तौल लिए देखा जा रहा है, जिसके ऊपर माटी माफिया लिखा हुआ है। इस तस्वीर को लेकर भाजपा उम्मीदवार स्वराज घोष ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि यह तस्वीर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जरिए तैयार कर सोशल मीडिया पर फैलायी गई है ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और उसकी सहयोगी संस्था आइपैक इस साजिश के पीछे है।

घोष ने बताया कि वे इस मामले में मोगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास जो हथियार है, वह वैध लाइसेंस के तहत है और राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। दूसरी ओर, माकपा उम्मीदवार और वकील अनिर्बान सरकार ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि तस्वीर वास्तविक है या एआई से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तस्वीरों का सोशल मीडिया पर प्रसार सामाजिक और कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है और यह साइबर अपराध के दायरे में आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तस्वीर कृत्रिम रूप से बनाई गई है, तो संबंधित व्यक्ति को कानून का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने उम्मीदवार के हलफनामे में दर्ज आपराधिक मामलों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों की सच्चाई का निर्धारण न्यायालय करेगा।

प्रथम प्रकाशन 1878
भारतमित्र

संपादकीय

महंगाई -बढ़ते दामों के बीच आम आदमी की जेब पर दोहरी मार

यह बात छिपी नहीं है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। रोजगार और आय के मामले में देश की बड़ी आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। यह विचित्र बात है कि एक ओर सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखने का दावा करती है, तो दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका सीधा असर आम आदमी पर जरूरी खर्च में कटौती और आर्थिक परेशानियों के रूप में देखने को मिल रहा है। जब आय के साधन सीमित हों, तो आम आदमी की यही अपेक्षा होती है कि जरूरी वस्तुओं के दाम उसकी पहुंच में हों, ताकि परिवार के भरण-पोषण का संकट पैदा न हो।मगर हाल के वर्षों में आमदनी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, जितनी तेजी से वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई मार्च में बढ़कर 3.4 फीसद हो गई, जबकि फरवरी में यह 3.2 फीसद के स्तर पर थी। खबरों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न संकट के कारण खुदरा महंगाई में वृद्धि हुई है। मगर सवाल है कि अगर सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित या स्थिर करने के लिए उचित कदम उठा रही है, तो फिर महंगाई में उछाल कैसे आ रहा है?यह बात छिपी नहीं है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। रोजगार और आय के मामले में देश की बड़ी आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। आमदनी में स्थिरता और घटती क्रयशक्ति की स्थिति में जब आवश्यक वस्तुओं पर आम लोगों का खर्च थोड़ा भी बढ़ता है, तो उनके लिए परेशानियां पैदा होना स्वाभाविक है। दरअसल, मार्च में महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा रहा।खुदरा महंगाई से इस बात का पता चलता है कि उपभोक्ताओं की खपत और खर्च की स्थिति क्या है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक अपनी नीति तय करते वक्त खुदरा महंगाई को ही आधार बनाता है। सरकार का दावा है कि खुदरा महंगाई अभी रिजर्व बैंक के चार फीसद के औसत अनुमान से नीचे बनी हुई है। मगर, यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि अगर महंगाई दर चार फीसद के दायरे से ऊपर जाती है, तो फिर कर्ज के सस्ता होने की उम्मीद भी कम हो जाती है।आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में फरवरी की तुलना में महंगाई दर का बढ़ना पश्चिम एशियाई संकट के शुरुआती प्रभाव का संकेत है। यानी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का मोर्चा फिर से खुलता है और यह स्थिति लंबे समय तक रहती है, तो आवश्यक वस्तुओं के दाम किस तेजी से बढ़ेंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में आलू-प्याज और कुछ दालों की कीमतों की महंगाई दर घटी है, लेकिन सोने-चांदी के आभूषण, नारियल, टमाटर और फूलगोभी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई।बिजली, गैस और अन्य ईंधन श्रेणी में खुदरा महंगाई मार्च में 1.65 फीसद रही, जबकि फरवरी में यह 1.52 फीसद के स्तर पर थी। यानी आम लोगों के लिए राहत कम और मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। यही नहीं, शहरी इलाकों में 3.11 फीसद की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.63 फीसदी रही, जहां रोजगार और आय के साधन सीमित होते हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय नहीं किए, तो आने वाले दिनों में यह संकट और ज्यादा गहराएगा।

फांसी जैसी सजा से ही रुकेंगी पुलिस हिरासत में मौतें

देश के न्यायालयों ने एक बार फिर पुलिस का वीभत्स चेहरा उजागर कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा के गठित किया गया पुलिस तंत्र किस कदर तानाशाह बन गया है, अदालतों के फैसलों ने इसे बेनकाब किया है। मदुरै की एक अदालत ने सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में बाप-बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी ज़ुर्माना भी लगाया गया है। तूतीकोरिन ज़िले के सातानुकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा। इसके बाद 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात क़रीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई।

(योगेंद्र योगी)

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं।

देश के न्यायालयों ने एक बार फिर पुलिस का वीभत्स चेहरा उजागर कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा के गठित किया गया पुलिस तंत्र किस कदर तानाशाह बन गया है, अदालतों के फैसलों ने इसे बेनकाब किया है। मदुरै की एक अदालत ने सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में बाप-बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी ज़ुर्माना भी लगाया गया है। तूतीकोरिन ज़िले के सातानुकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा। इसके बाद 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात क़रीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

इसी तरह लुधियाना जिले में करीब छह साल पहले रिकवरी एजेंट दीपक शुक्ला की थाना डिविजन नंबर 5 की पुलिस हिरासत में हुई थी। मौत के मामले में लुधियाना की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं। यह पूरा मामला फरवरी 2020 का है, जब पुलिस ने दीपक शुक्ला को वाहन चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया था। दीपक पर चोरी का झूठा मामला दर्ज कर उसे अमानवीय यातनाएं दीं। 26 फरवरी 2020 की रात दीपक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिसिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। दीपक के परिवार ने इंसाफ के लिए एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी।

पंजाब के मोगा जिले में भिंदर सिंह की मौत गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं देने से हुई थी। न्यायिक जांच में सामने आया कि भिंदर सिंह को कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं दी गईं। इस मामले में स्थानीय अदालत ने पंजाब पुलिस के पांच कर्मियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में ट्रायल चलाने का आदेश देते हुए केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया है। जुलाई 2024 को मध्यप्रदेश के बिलाखेड़ी निवासी युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने 8 लाख रुपये की कथित चोरी के आरोप में उसे हिरासत में लिया था। हिरासत में मौत के बाद उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके परिणामस्वरूप 15 मई को सीबीआई जांच का आदेश जारी हुआ। इस जांच के सिलसिले में एजेंसी ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हिरासत में हुई मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाने वाले दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभी भी फरार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं। शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। 4 सितंबर को दिए गए अपने आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि राजस्थान में आठ महीनों में 11 हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट सामने आई है।कोर्ट ने कहा कि इससे साफ़ है कि हिरासत में अत्याचार कम होने के बजाय जारी हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराज़गी जताई थी। केंद्र सरकार ने एक भी रिपोर्ट जमा नहीं की। जस्टिस नाथ ने इस पर कड़ा एतराज़ जताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार अदालत के आदेशों को हल्के में

नहीं ले सकती। उन्होंने पूछा, केंद्र सरकार अदालत को बहुत हल्के में ले रही है, क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच भारत में हिरासत में 11,650 मौतें हुईं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,630 हिरासत में मृत्युएँ दर्ज की गईं, जो देश में सबसे अधिक है। आंकड़ों के 2023 के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017 और 2022 के बीच, हिरासत में हुई मृत्युओं के संबंध में देश भर में केवल 345 मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप केवल 123 गिरफ्तारियाँ हुईं। एनएचआरसी के आंकड़ों से पता चलता है कि 1996 और 2018 के बीच हिरासत में हुई 71 प्रतिशत मौतें गरीब या कमज़ोर पृष्ठभूमि के बंदियों की थीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 के फैसले में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अनिवार्य सुरक्षा उपाय निर्धारित किए थे। जिसके तहत रिश्तेदारों को सूचित करना, गिरफ्तारी ज्ञापन रखना, चिकित्सा परीक्षण, कानूनी परामर्श, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य था। इन दिशा–निर्देशों को अनुच्छेद 141 के अंतर्गत प्रवर्तनीय कानून माना जाता है। न्यायालय का यह आदेश कहीं धूल फांक रहा है। न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में गठित भारतीय विधि आयोग ने 30 अक्टूबर, 2017 को तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को सौंपी गई अपनी 273 वीं रिपोर्ट में केंद्र सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के यातना-विरोधी सम्मेलन की पुष्टि करने और यातना निवारण कानून लागू करने की सिफारिश की थी।

आयोग ने यातना निवारण के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत किए हैं। इस रिपोर्ट में यातना निवारण विधेयक के अलावा विधि आयोग ने यातना उन्मूलन के उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। रिपोर्ट में यातना के खतरे को कम करने और यातना के कृत्यों पर रोक लगाने और ऐसे कृत्यों के अपराधियों के लिए कठोर दंड की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट के साथ संलग्न विधेयक के मसौदे में आजीवन कारावास और जुर्माने तक के दंड का प्रावधान था। आयोग ने न्यायसंगत मुआवजे का निर्णय न्यायालयों पर छोड़ दिया। इसके अलावा, आयोग ने यातना पीड़ितों, शिकायतकर्ताओं और यातना के मामलों के गवाहों को संभावित खतरों, हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश भी की गई थी।

1997 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र यातना-विरोधी सम्मेलन की पुष्टि नहीं की। इसकी पुष्टि करने का अर्थ यह होता कि भारत को यातना निवारण विधेयक पारित करना होगा, जिसे पहली बार 2010 में यूपीए द्वितीय सरकार द्वारा पेश किया गया था। इसमें किसी लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक की सहमति से ऐसा कृत्य, जिससे गंभीर चोट पहुंचे या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को खतरा हो। इसमें जबरन कबूलनामा करवाने के उद्देश्य से, या धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, समुदाय या किसी अन्य आधार पर दंडित करने के लिए दी गई यातना के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की सजा का प्रस्ताव था, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विधेयक आज तक कानून नहीं बन पाया।

इससे साफ जाहिर है जो भी दल सत्ता में आता है, वह देश के मौजदा पुलिस सिस्टम में बदलाव नहीं करना चाहता। कारण साफ है यदि ऐसे कानून बन जाएंगे तो पुलिस अधिकारी नेताओं के इशारे पर नहीं नाचेंगे। जब नाचेंगे नहीं तो नेताओं के मौखिक तौर पर गैर कानूनी काम कैसे होंगे। यही वजह रही है कि केंद्र ने हाल ही में दंड संहिता को न्याय संहिता का नाम दे दिया है। इसमें पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। पुलिस अफसरों को लापरवाही बरतने और सही तरीके से ड्यूटी को अंजाम नहीं देने पर जेल भेजे जाने का प्रावधान नहीं किया गया। पुलिस हिरासत में मौतों का इस कानून में जिक्र तक नहीं किया गया। उल्टे पुलिस हिरासत में जब–जब मौतों का मामला सामने आता है, सरकार और पुलिस अफसर उसके रफा दफा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। सत्तारुढ राजनीतिक दलों की मिलीभगत का ही परिणाम है कि आज 21वीं सदी में भी भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें आदिम युग की याद दिलाती हैं।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

लेकिन शहरी माओवाद पर कैसे लगे लगाम?

(उमेश चतुर्वेदी)

मोदी सरकार के बाद राष्ट्रवादी विचारधारा को उम्मीद थी कि सत्ता केंद्रों और संस्थानों से इस विचारधारा की विदाई हो जाएगी। लेकिन अब भी यह विचारधारा प्रभावी तौर पर उपस्थित है। इस विचारधारा के कतिपय क्रांतिकारियों ने तो अब चोला तक बदल लिया है और मौजूदा सत्ता तंत्र में भागीदार भी बन चुके हैं।

बीते तीस मार्च को गृहमंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के रूप में कुख्यात रहे माओवादी और नक्सली आतंकवाद के खात्मे का औपचारिक अंत की घोषणा कर दी है। चाहे माओवाद हो या नक्सलवाद, दोनों ही धाराएं उग्रपंथी वामपंथ से प्रभावित रही हैं। इनका मानना रहा है कि सत्ता बंदूक की नली या बारूद से निकलती है। इसी विचारधारा के तहत इस वैचारिकी ने भारत के तकरीबन एक तिहाई जिलों पर अरसे तक कब्जा जमाए रखा। इस विचारधारा से प्रभावित लाल आतंक एक दौर में पशुपति से लेकर तिरूपति तक फैला हुआ था। लेकिन अब यह निस्तेज हो चुका है। ज्यादातर नक्सली या माओवादी लड़ाके या तो हथियार डाल कर मुख्यधारा की जिंदगी में वापस लौट गए हैं या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए हैं। लेकिन अब भी इस विचारधारा से प्रभावित एक वर्ग बचा हुआ है। जिसका सत्ता के प्रतिष्ठानों पर भले ही प्रभाव ना हो, लेकिन तंत्र पर उसका प्रभाव अब भी है। भारत खबर अपडेट

मार्च 2022 में जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म आई थी। 'द कश्मीर फाइल्स' नामक इस फिल्म में एक संवाद है, सत्ता भले ही उनकी है, लेकिन सिस्टम अपना है। इस संवाद में जिस सिस्टम की ओर इशारा है, दरअसल तंत्र पर उसका ही प्रभाव है। कहना न होगा कि यह प्रभावी तबका वैसी ही उग्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, जिसके बारूदी रूख के अंत का ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने किया है। कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में सक्रिय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिज्ञासु कार्यकर्ताओं ने इसे 'अर्बन नक्सल' कहा था। अर्बन यानी शहरी नक्सल। याद कीजिए, छह अप्रैल 2010 की घटना, जब बस्तर में सीआरपीएफ के 74 जवानों को घेरकर नक्सलियों ने बारूदी सुरंगों के जरिए उड़ाकर मार डाला था। इस लोमहर्षक कार्रवाई भारतीय राष्ट्र राज्य पर अर्बन नक्सल समुदाय ने बड़ी जीत के रूप में देखा था। राजधानी दिल्ली में लाल गढ़ के रूप में विख्यात जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने इस कार्रवाई पर खुलेआम खुशियां जताई थीं। तमाम विश्वविद्यालयों के वामपंथी प्रोफेसरों और छात्रों के एक समूह ने इस लोमहर्षक हत्या कांड को भारतीय राज व्यवस्था पर नक्सली जीत के रूप में लिया था। बस्तर की इस घटना के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार सकते में थी। उसने समानांतर सत्ता चला रहे नक्सली और माओवादी आतंकियों पर हवाई कार्रवाई करने का विचार शुरू कर दिया था। लेकिन शहरी इलाकों के वामपंथी बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध शुरू किया। तंत्र में इनकी उपस्थिति कितनी प्रभावी है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनमोहन सरकार ने नक्सली हिंसा का प्रभावी जवाब देने का विचार त्याग दिया था।

नक्सलवाद कहें या माओवाद या फिर वामपंथ की कोई अन्य धारा, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, पत्रकारिता, स्वयंसेवी संगठनों, वकालत, अस्पतालों, प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारीतंत्र में भी इनके प्रभावी लोग अब भी मिल जाएंगे। अरूंधती रॉय, हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण जैसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवी तो खुद ही मानते हैं कि वे इस विचारधारा से हैं।

तंत्र में इस विचारधारा के प्रभावी होने की शुरूआत 1969 में कांग्रेस के विभाजन से होती है। तब अपनी केंद्रीय सत्ता को बचाने के लिए इंदिरा गांधी को वामपंथी दलों के सहयोग की जरूरत थी। उन्होंने सहयोग किया भी, बदले में शैक्षिक संस्थानों पर उनका प्रभाव बढ़ा। इसकी वजह यह रही कि इंदिरा सरकार ने शोध और शैक्षिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को इन्हीं के हवाले कर दिया। इस विचारधारा ने अपने ही लोगों को इन संस्थानों में खूब भरा।

2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो यह वैचारिकी पहले सकते में रही। बाद में इसने रणनीति और पैंतरा बदला। शुरू में तो इस विचारधारा ने कभी पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में वैचारिकी आधारित आंदोलन छेड़ा तो कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों से छेड़खानी के बहाने राष्ट्रवादी विचाराधारा को निशाने पर लेकर आंदोलन चलाया। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित बेमुला के बहाने राष्ट्रवादी शासन व्यवस्था के दौरान कथित तौर पर दलितों और पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप लगाकर वैचारिक आंदोलन खड़ा किया। दो कृषि कानूनों के बदलाव के विरोध में लंबे समय तक चले किसान आंदोलन को भी इस वैचारिकी का खुला समर्थन रहा। टूल किट गिरोह इसी दौरान बेपर्दा हुए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर के अल्पसंख्यकों को भड़काने और उन्हें आंदोलन में लाने के पीछे भी यही विचारधारा रही। इन आंदोलनों के लंबे समय तक चलने, इनके लिए लोगों के एकत्रित होने की वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी नक्सलियों का कितना बड़ा नेटवर्क है और कितनी गहराई तक उनकी पहुंच है। मोदी सरकार के बाद राष्ट्रवादी विचारधारा को उम्मीद थी कि सत्ता केंद्रों और संस्थानों से इस विचारधारा की विदाई हो जाएगी।

क्या नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक, प्रशासनिक व राजनीतिक सांठगांठ जिम्मेदार है?

> आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से किस कदर श्रमजीवी मजदूरों का शोषण अनवरत रूप से जारी रहता है और फिर एक दिन नोएडा मजदूर आंदोलन के शक्ल में फूट पड़ता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। इसी प्रवृति से नई आर्थिक नीति विफलता के कगार पर खड़ी है। नीति निर्माण में नेताओं/नौकरशाहों ने जो पक्षपात दिखाया है, वह सभी समस्याओं की जड़ है। यक्ष प्रश्न यह कि जिस देश में महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और खर्चीला शहरी जीवन का बोलबाला हो, वहां पर निजी क्षेत्र के असमान वेतन स्तर के लिए हमारे नीति निर्माता जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है, वही बताएं।

(कमलेश पांडे)

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है।

हमारे देश के राजनेता भले ही चुनावों के दौरान दलित-महादलित-आदिवासी, ओबीसी-ईबीसी, अल्पसंख्यक-पसमांदा और गरीब सवर्ण आदि से जुड़े सामाजिक न्याय सम्बन्धी तरह-तरह की बातें करते हैं, ममनगढ़ंत आंकड़े गिनाते/बताते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे श्रमजीवियों का अंतहीन शोषण होता रहता है, जिससे उनका मुंह फेरे रहना या फिर किसी बड़े आंदोलन के बाद सक्रिय होना उनके नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल उठाता है।

आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से किस कदर श्रमजीवी मजदूरों का शोषण अनवरत रूप से जारी रहता है और फिर एक दिन नोएडा मजदूर आंदोलन के शक्ल में फूट पड़ता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। इसी प्रवृति से नई आर्थिक नीति विफलता के कगार पर खड़ी है। नीति निर्माण में नेताओं/नौकरशाहों ने जो पक्षपात दिखाया है, वह सभी समस्याओं की जड़ है।

यक्ष प्रश्न यह कि जिस देश में महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और खर्चीला शहरी जीवन का बोलबाला हो, वहां पर निजी क्षेत्र के असमान वेतन स्तर के लिए हमारे नीति निर्माता जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है, वही बताएं। विपक्ष का काम संसद में, विधान मंडल में इन्हीं पहलुओं पर तर्कसंगत बहस करना है, लेकिन वह भी नीतिगत नकारापन का शानदार नमूना बन चुका है। दिलचस्प तो यह कि पहले सत्ताधारी यूपीए के वक्त एनडीए विपक्ष में था और अब सत्ताधारी एनडीए के वक्त यूपीए/इंडिया गठबंधन विपक्ष में है।

चूंकि दोनों पूंजीवादी गठबंधन हैं और अपने आर्थिक मोहपाश में जनोन्मुखी समाजवादी व वामपंथी सियासत को बांध चुके हैं, जिससे सबकुछ गड्डमड्ड हो चुका है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद और कहीं सम्प्रदायवाद के नाम पर परस्पर बंटी हुई जनता को अपनी मौलिक जरूरतों का एहसास ही नहीं है।

काबिलेगौर है कि शहरों/महानगरों या गांवों में जो आमतौर पर वेतन स्ट्रक्चर होता है, उससे कोई युवा या वयस्क अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन कर सकता है क्या? जवाब होगा- संभव नहीं ! कोढ़ में खाज यह कि तरह तरह के मित्रों- शिक्षा मित्र, स्वास्थ्य मित्र आदि के मार्फ़त सरकारी क्षेत्र भी इन्हीं पूंजीवादी मानसिकता को तरजीह देता आया है, जिस पर उदार हृदय से बहस करने और भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने की जरूरत है।

सवाल है कि जिन शहरों में फ्लैट्स या जमीन की कृत्रिम कीमतें आसमान छूती हों, वहां के दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी, अंशकालिक/पूर्णकालिक श्रमिकों के वेतनमान, और भारतीय कानूनों से अधिकारियों/उद्योगपतियों के खिलवाड़ से पूरी श्रम व्यवस्था विस्फोटक कगार पर खड़ी है। शहरों में बढ़ता झुग्गी-झोपड़ी कल्चर किसी नैतिक महामारी जैसा प्रतीत होता है।

सुलगता सवाल है कि निजी क्षेत्र में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और पेंशन आदि की सुविधाएं निजी कम्पनियों में मिलती है। प्रोपर्टी इंडस्ट्री की तरह आधा ब्लैक सैलरी और आधा व्हाइट सैलरी वाली आंखों में धूल झोंकने वाली व्यवस्था से खुफिया तंत्र अनजान क्यों है? सरकारी क्षेत्रों की तरह आवासीय सुविधाओं से निजी क्षेत्र के श्रमिकों को वंचित क्यों रखा जाता है? नौकरी बाजार में श्रम ठेकेदार पैदा करने से किसके हित सधते हैं? सवाल अनेक हैं, लेकिन उत्तर एक- राजनीतिक, प्रशासनिक और औद्योगिक सांठगांठ से जारी नीतिगत भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी है, जो किसी बड़ी जनक्रांति के बाद ही करवट लेगी।

जरा कल्पना कीजिए कि जब नरेंद्रमोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी मजदूर विरोधी परिस्थिति है तो पूर्व की सरकारों में कैसा जंगलराज रहा होगा, विचारणीय पहलू है। मजदूर शोषण कांड की एसआईटी और न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम भारतीयों के भविष्य के साथ एफडीआई आकर्षित करने के चक्कर में घोर अन्याय हो रहा है, जिससे बचे जाने की जरूरत है।

अब नोएडा में मजदूरों के हिंसक आंदोलन के राजनीतिक निहितार्थ की बात करते हैं। चूंकि नोएडा में मजदूरों का हिंसक आंदोलन वेतन वृद्धि की मांग पर केंद्रित है, जो हरियाणा की 35 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी से प्रेरित है। लिहाजा, योगी सरकार को तुरंत इसे लागू करना चाहिए। बताया गया कि यह प्रदर्शन फेज-2 होजरी कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर पूरे नोएडा में फैल गया, जहां पेशेवर विपक्षी आंदोलनों के तर्ज ओर तोड़फोड़ और आगजनी हुई।

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है। यही वजह है कि योगी सरकार ने संवाद के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है और अविलंब इसके निर्णयों को लागू करने की जरूरत है।

जहां तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं की बात है तो योगी सरकार ने आंदोलन को साजिश, नक्सलवाद या राजनीतिक हाथ बताया, जिससे सहमत होना मुश्किल है, लेकिन आंदोलन के हिंसक होने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत भी नहीं हैं। वहीं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की पूंजीपति पक्षधर नीति को जिम्मेदार ठहराया और मजदूर शोषण का आरोप लगाया, जो अतिरेक है। चूंकि कांग्रेस और सपा ने सरकार की आलोचना की, इसलिए केंद्र भी सतर्क है।

इस अप्रत्याशित आंदोलन का प्रमुख निहितार्थ यह है कि यह आंदोलन श्रम नीतियों पर बहस तेज कर सकता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के फैसलों से अंतरराज्यीय दबाव बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष को मजदूर वोट बैंक मजबूत करने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को कानून-व्यवस्था पर खुद को साबित करने की चुनौती बढ़ी।दिल्ली-एनसीआर में इसके फैलाव का खतरा है, जो आगामी चुनावों में यदि बड़ा मुद्दा बना तो सत्ताधारी भाजपा के लिए 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव में राजनीतिक मुश्किलों का कारण बन सकता है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकार समय रहते ही सचेत हो जाएं। इसी में राजनीतिक बुद्धिमानी होगी। यह कोरा सच है कि नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक-प्रशासनिक-राजनीतिक सांठगांठ जिम्मेदार है। नोएडा मजदूर आंदोलन 2027 यूपी विधानसभा चुनावों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह श्रमिक असंतोष को विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बना रहा है। हालांकि अभी ताजा घटना होने से विश्लेषण अनुमानित हैं, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। इससे विपक्ष को लाभ मिलता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की पूंजीपति नीति बताकर मजदूरों का समर्थन किया, जो पीडीएयानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत कर सकता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, और विपक्षी एकता का संकेत दिया। नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक वोट (गौतमबुद्धनगर सीटें) प्रभावित हो सकते हैं। इससे भाजपा की जमीनी चुनौती बढ़ेगी और हिंदुत्व दम तोड़ देगा, इसलिए योगी सरकार ने वेतन, ओवरटाइम सम्बन्धी निर्देश देकर क्षतिपूर्ति की कोशिश की, लेकिन इसे साजिश बताकर विपक्ष को और हवा मिली। कानून-व्यवस्था का सवाल उठा, जो भाजपा के मजबूत सरकार वाले नैरेटिव को कमजोर करता है। इससे दिल्ली-एनसीआर में आंदोलन के फैलाव से पश्चिम यूपी की सीटें जोखिम में पड़ सकती हैं। वहीं, श्रम मुद्दा, बढ़ती महंगाई-बेरोजगारी से जुड़कर 2027 में प्रमुख हो सकता है, खासकर ग्रेटर नोएडा-जेवर जैसे क्षेत्रों में। इसलिए यदि समाधान न हुआ तो विपक्ष मजबूत, वरना भाजपा इसे विकास के पक्ष में पलट सकती है। कुल मिलाकर, नोएडा रणभूमि बन चुका है।वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

प्रधानमंत्री मोदी ने हरिवंश को तीसरी बार उपसभापति बनने पर दी बधाई, अनुभव और कार्यशैली को सराहा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश के लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी और इसे सदन के गहरे विश्वास का प्रतीक बताया। राज्यसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश का पुनर्निर्वाचन उनके अनुभव, संतुलित कार्यशैली और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता की स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि उपसभापति के रूप में हरिवंश ने न केवल सदन की कार्यवाही का कुशल संचालन किया है, बल्कि अपने पूर्व अनुभवों से सदन को समृद्ध भी किया है, जिससे सदन का माहौल और अधिक परिपक्व हुआ है। मोदी ने कहा, ÷राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना अपने आप में इस सदन का आपके (हरिवंश) प्रति गहरा विश्वास दर्शाता है। साथ ही, बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव से सदन को जो लाभ प्राप्त हुआ है, उसका भी यह प्रमाण है। सदन को साथ लेकर चलने का जो आपका प्रयास रहा है, उस पर सदन ने एक प्रकार से अपनी मोहर लगा दी है। यह वास्तव में आपके अनुभव और योगदान का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनका नया कार्यकाल भी समर्पण, संतुलन और गरिमा के साथ आगे बढ़ेगा और सदन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि हरिवंश ने राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अपना अधिकांश समय संसदीय कार्यों को समर्पित किया है और सभापति की अनुपस्थिति में वे कुशलतापूर्वक सदन का संचालन करते रहे हैं।उन्होंने हरिवंश के सार्वजनिक जीवन और पत्रकारिता में योगदान की भी सराहना करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली में स्पष्टता, विनम्रता और शालीनता का समन्वय दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने विधानसभाओं और विधान परिषदों के अधिकारियों के प्रशिक्षण में उनके योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 21वीं सदी के इस दूसरे क्वार्टर में इस सदन को बहुत करना है। देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस कारण पीठाधीश सहित हम सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 200 नई इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा को ईस्ट विनोद नगर डिपो में आयोजित कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने मदनपुर खादर में नए बस टर्मिनल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने डीटीसी ईस्ट विनोद नगर डिपो में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इस मौके दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को हरित, स्मार्ट और स्वच्छ बनाने की दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में आज 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ोतरी के साथ डीटीसी प्लीट की संख्या बढ़कर लगभग 6300 बसों तक पहुंच गई है।

दिल्ली में प्रदूषण-मुक्त सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए आज ईस्ट विनोद नगर डिपो से 200 नई ईवी बसों को दिल्ली की सेवा में समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मिशन मोड में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ईवी में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य कर रही है। दिल्ली में ईवी बसों की संख्या 4500 से अधिक हो चुकी है और 2026 के अंत तक इसे 7000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली से रोहतक रूट आईएसबीटी कश्मीरी गेट और पीरागढ़ी चौक से होकर गुजरेगा, जिसमें टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, रोहद, सांपला और रोहतक बस स्टैंड जैसे प्रमुख पड़ाव शामिल है।

ईरान से भारत ने निकाले 2361 लोग : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली भारत ने पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक ईरान से अपने एवं मित्र देशों के 2361 नागरिकों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते से सुरक्षित निकाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, संघर्ष के प्रकोप के बाद से हमने 2,361 नागरिकों को ईरान से सुरक्षित रूप से निकालने में मदद की है। इनमें से 2,060 आर्मेनिया के माध्यम से और 301 अज़रबैजान के माध्यम से आए हैं। इन 2,361 लोगों में 1,041 भारतीय छात्रों के साथ-साथ तीन विदेशी भी शामिल हैं। एक बांग्लादेश से, एक श्रीलंका से और एक गुयाना से है। उन्होंने कहा कि ईरान में अभी भी 6000 से 7000 भारतीय मौजूद हैं। पश्चिम एशिया संकट पर एक अंतर-मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन ने भी कहा, ÷सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकास की निगरानी करना जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय में एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष परिचालन कर रहा है और हमारे मिशनों के साथ समन्वय में काम कर रहा है। स्थानीय सरकार के दिशानिर्देशों, उड़ान और यात्रा की स्थिति, कांसुलर सेवाओं और हमारे समुदाय का समर्थन करने के लिए किए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों से संबंधित जानकारी के साथ अद्यतन सलाह जारी की जा रही हैं। महाजन ने कहा कि इस क्षेत्र से भारत के लिए उन देशों से उड़ानें जारी हैं जहां हवाई क्षेत्र खुला है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अब तक ईरान से आर्मेनिया और अज़रबैजान तक 2,358 भारतीय नागरिकों की भारत की आगे की यात्रा के लिए आवाजाही की सुविधा प्रदान की है। इज़राइल का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से प्रतिबंधित उड़ान संचालन के साथ खुला है। हम जॉर्डन और मिस्र के माध्यम से इज़राइल से भारतीय नागरिकों की यात्रा को भारत तक सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे पड़ोसी देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को अपने कई पड़ोसियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो ऊर्जा संसाधन प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। हम पहले से ही कई देशों को ऊर्जा संसाधन प्रदान कर रहे हैं। हालाँकि, यह हमारी अपनी जरूरतों और यहाँ हमारे संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने मार्च में बांग्लादेश को 22,000 मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल प्रदान किया... श्रीलंका को, हमने पिछले महीने उन्हें 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद भेजे थे। एक सप्ताह पहले, हमारे विदेश मंत्री ने मॉरीशस का दौरा किया था। उस समय के दौरान, इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई और हम वर्तमान में मॉरीशस की ऊर्जा स्थिति में सुधार करने और इसे तेल और गैस प्रदान करने के लिए दोनों देशों के बीच सरकार से सरकार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। जायसवाल ने कहा कि इसी तरह से नेपाल और भारत के बीच मौजूदा समझौते हैं, एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल के बीच, जिसके तहत हम उन्हें पेट्रोलियम उत्पाद प्रदान करते हैं और ये उन्हें बिना किसी रुकावट के उनकी जरूरतों के अनुसार प्रदान किए जा रहे हैं। इसी तरह, भूटान के साथ, हमारे पास एक समझ और साझेदारी है। हम उन्हें ऊर्जा उत्पादों के संबंध में भी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मॉरीशस और सेशेल्स के बारे में, हमें उनसे कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं और हम इस मामले पर उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं।

पूर्व रेलवे

ई-निविदा सं.: 15_2026-27, 16_2026-27 दिनांक 15.04.2026; सीनि. डीईएन/2/हावड़ा, पूर्व रेलवे, हावड़ा, डीआरएम बिल्डिंग, हावड़ा रेलवे स्टेशन के निकट, हावड़ा-711101 द्वारा सीनि. डीईएन/2/हावड़ा के अधीन नीचे उल्लेखित कार्य के निष्पादन के लिए सिंचाई/सीपीडब्ल्यूडी/एसईबी/एमईएस अथवा अन्य किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ पंजीकृत सहित समतुल्य प्रकृति के कार्य का अनुभव एवं वांछित वित्तीय क्षमता रखने वाले निविदादाताओं से निम्नलिखित ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं। **क्रमांक एवं ई-निविदा सं.; कार्य का विवरण; अनुमानित लागत; बयाना राशि:** (1) 15 _2026-27; एईएन/डानकुनी के अधीन एसएसई/डब्ल्यू/डानकुनी के अधिकार क्षेत्र में चंदनपुर एवं शिवाईचंडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ऊंचा करना एवं वर्तमान सतह का विकास; रु. 2,85,72,797.63 रु. 5,71,500; (2) 16_2026-27; एईएन/डानकुनी अनुभाग के कमारकुण्डु, चंदनपुर, गुड़ाप, बेलमुड़ी एवं जौग्राम में स्टाफ क्वार्टर, जल आपूर्ति का नवीनीकरण तथा रखरखाव कार्य तथा विविध कार्य तथा बेलानगर स्टेशन में डीसी ट्रैक सर्किट के स्थान पर ड्युअल डिटेक्शन प्रारूप में ड्युअल एमएसडीएसी का प्रावधान; रु. 2,08,69,790.17; रु. 4,17,400; **निविदा प्रपत्र की कीमत:** शून्य (दोनों के लिए)। **समापन अवधि:** 12 महीने (दोनों के लिए)। **निविदा बंद होने की तारीख एवं समय:** 11.05.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक (दोनों के लिए)। निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित बंद होने की तारीख को किसी भी कारणवश छुट्टी का दिन/बंद/हड़ताल घोषित होने पर भी ऑनलाइन निविदा बंद होने की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चूंकि आईआरईपीएस की वेबसाइट में एप्लीकेशन निविदा बंद होने की तारीख एवं समय के उपरांत कोई भी प्रस्ताव जमा करने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि, ऑनलाइन निविदा अगले कार्यकारी दिवस को खोली जाएगी। निविदाओं का विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदादाताओं से अपने प्रस्ताव उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करने का अनुरोध किया जाता है। मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(HWH-26/2026-27)

निविदा सूचनाएं वेबसाइट **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in** पर भी उपलब्ध है

हमें अनुसरण करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/(सामान्य), पूर्व रेलवे, सियालदह, दूसरी मंजिल, रिमोट कंट्रोल बिल्डिंग, डीआरएम बिल्डिंग, कैजर स्ट्रीट, सियालदह, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए नीचे उल्लेखित ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **क्रमांक 1, निविदा सं.: ईएलईजी-ओटी-1312-2025-26, दिनांक 16.04.2026, कार्य का विवरण:** रानाघाट में मालगाड़ी परीक्षण सुविधाओं के लिए विद्युतीय एवं संबंधित सुविधाएँ। **निविदा मूल्य:** रु. 1,11,79,798.00। **बयाना राशि:** रु. 2,23,600। **समापन अवधि:** 08 महीने। **क्रमांक 2, निविदा सं.: ईएलईजी-ओटी-1314-2025-26, दिनांक 16.04.2026, कार्य का विवरण:** बालीगंज (बीएलएन) में मालगाड़ी परीक्षण सुविधा का विकास। **निविदा मूल्य:** रु. 1,45,13,703.00। **बयाना राशि:** रु. 2,90,300। **समापन अवधि:** 08 महीने। **क्रमांक 3, निविदा सं.: ईएलईजी-ओटी-1315-2026-27, दिनांक 16.04.2026, कार्य का विवरण:** एसएसई/ई/जी/सियालदह-II के अधिकार क्षेत्र के अधीन न्यू अलीपुर ब्लॉक सं. 1 से 5 में पैसेंजर लिफ्टों (निर्माता-ओटिस) का तीन (03) वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध। **निविदा मूल्य:** रु. 15,78,988.20। **बयाना राशि:** रु. 31,600। **समापन अवधि:** 36 महीने। **क्रमांक 4, निविदा सं.: ईएलईजी-ओटी-1316-2025-26, दिनांक 16.04.2026, कार्य का विवरण:** बिशरपाड़ा कोदालिया से पेट्रापोल अनुभागों में वर्तमान विद्युतीय सामान्य सम्पत्तियों के लिए विकास/उन्नयन/सुधार कार्य। **निविदा मूल्य:** रु. 31,26,950.00। **बयाना राशि:** रु. 62,500। **समापन अवधि:** 12 महीने। **आईआरईपीएस पर निविदा प्रकाशन तिथि:** क्रमांक 1 से 4 के लिए दिनांक 15.04.2026। **बोली शुरू होने की तारीख:** क्रमांक 1 से 4 के लिए दिनांक 24.04.2026। **निविदा बंद होने की तारीख एवं समय:** क्रमांक 1 से 4 के लिए 08.05.2026 को अपराह्न 02.00 बजे। निविदा सूचना का विवरण एवं समय-समय पर जारी संशोधनी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

(SDAH-10/2026-27)

निविदा सूचनाएं वेबसाइट **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in** पर भी उपलब्ध है

हमें अनुसरण करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा, सत्ता पक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द के इस्तेमाल पर सत्ता पक्ष ने तीखी आपत्ति जताई, जिसके चलते सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि देश की जनता का अपमान है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुनकर इस पद पर बैठाया है और इस तरह की भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए और उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बातें सार्वजनिक मंचों पर कही जाती हैं, उन्हें उसी रूप में संसद में दोहराना उचित नहीं है।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है और इस प्रकार की बयानबाजी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। विवाद के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान का बचाव करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर सच्चाई सामने लाने की जरूरत है और सरकार देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा और आरोप केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाए जा रहे हैं, जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे-निविदा

निविदा सूचना सं.: पीसीएमएम/जीईएनएल/टीपी/2026/12, दिनांक 17.04.2026; भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, मुख्यालय (पांचवीं मंजिल), न्यू प्रशासनिक भवन, 11, गार्डनरीच रोड, कोलकाता-700043 द्वारा "ई" प्रोक्योरमेंट प्रणाली के लिए खुली ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसे वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर अपलोड कर दिया गया है। सभी निविदाएं अपराह्न 2.00 बजे बंद कर दी जाएगी।

क्र.	निविदा सं.	बंद होने की तिथि	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	ईएमडी (रु. में)
1	66255017बी	30.04.2026	टंगस्टन कार्बाइड टेम्पिंग टूल (टीसीटीटी) इत्यादि	15 सेट	1,96,430/-
2	33263459	20.05.2026	एलएचबी जीएस कोचों इत्यादि के लिए सेंटरिंग डिस्क	652 अदद	1,07,710/-
3	33263170	07.05.2026	अर्थिंग ब्रश असेम्बली के लिए सम्पूर्ण हाउसिंग इत्यादि	2200 अदद	1,42,160/-
4	60260001	11.05.2026	25टी कंक्रीट स्लीपर पर ईआरसी एमके-V के साथ प्रयोग हेतु मेटल लाइनर का निर्माण एवं आपूर्ति	620000 सेट	7,68,180/-
5	38264051ए	04.05.2026	कैसनब 22एचएस (मोड 1) बोगी के लिए आउटर बोलस्टर सस्पेंशन स्प्रिंग	7000 अदद	2,54,410/-
6	आईई 265066ए	13.05.2026	एचटी थ्री कोर पावर केबल 2000 मीटर	2000 मीटर	1,46,130/-
7	आईएच 256113बी	06.05.2026	इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिजों की आपूर्ति, स्थापना एवं चालू करना	2 अदद	66,100/-
8	79261779	07.05.2026	सभी एसी कोचों इत्यादि के लिए अग्नि रोधक कर्टन फैब्रिक	15320 मीटर	1,28,370/-
9	65255028	26.05.2026	चक्रधरपुर एवं रांची के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर के साथ सहायक उपकरण। (बोली-पूर्व बैठक 05/05/26 को 12:00 बजे पीसीएमएम सभा कक्ष/द.पू. रेलवे/गार्डनरीच/कोलकाता-43 में आयोजित होगी)	06 अदद	8,06,250/-
10	65255050	19.05.2026	हॉट फॉस्फेटिंग संयंत्र साथ में सहायक उपकरण। (बोली-पूर्व बैठक 29/04/26 को 16:00 बजे पीसीएमएम सभा कक्ष/द.पू. रेलवे/गार्डनरीच/कोलकाता-43 में आयोजित होगी)	01 अदद	3,91,230/-
11	65255046	21.05.2026	क्वायल स्प्रिंग के लिए एयरलेस सेंट्रिफ्यूगल शॉट पीनिंग संयंत्र की आपूर्ति एवं स्थापना (बोली-पूर्व बैठक 05/05/26 को 16.00 बजे पीसीएमएम सभाकक्ष/द.पू. रेलवे/गार्डनरीच/कोलकाता-43 में आयोजित होगी)	02 अदद	2,43,040/-
12	67255001	14.05.2026	10 टन क्षमता वाली 02 (दो) अदद सामग्री वाहक ट्रकों की आपूर्ति के साथ सुधार कार्य (बोली-पूर्व बैठक 28/04/26 को 12:00 बजे पीसीएमएम सभा कक्ष/द.पू. रेलवे/गार्डनरीच/कोलकाता-43 में आयोजित होगी)	02 अदद	1,24,340/-
13	29254855बी	27.04.2026	वाइंडिंग वायर फ्लैट एफआई सीयू एफओ13	3300 किग्रा	1,09,120/-
14	25253721	28.05.2026	लोको कैब मीटरों का सेट	39 सेट	1,13,510/-

इच्छुक निविदादातागण निविदाओं के सम्पूर्ण विवरण/ब्यौरा/विनिर्देश के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देख सकते हैं तथा अपनी बोलियाँ ऑनलाइन जमा करें। किसी भी परिस्थिति में इन मदों के लिए मैनुअल निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। **वि.द्र.:** प्रत्याशित बोलीदातागण अन्य सभी निविदाओं में भाग लेने तथा तदुपरांत प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र के लिए नियमित रूप से **www.ireps.gov.in** देख सकते हैं। **(PR-57)**

नेपाल में पिछले साल जेनजी प्रदर्शन के दौरान मारे गए 7 लोगों की अब तक नहीं हुई पहचान

काठमांडू। नेपाल में पिछले वर्ष सितंबर में हुए जेनजी प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों में से 7 शवों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के एसपी तथा प्रवक्ता पवन भट्टराई ने बताया कि जेनजी प्रदर्शन के दौरान केवल काठमांडू में ही 49 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 7 शवों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि 42 शवों की पहचान कर संबंधित परिवारों को सौंप दिए गए हैं। काठमांडू के बौद्ध स्थित भाट भटेनी सुपर मार्केट में लगी आग में झुलसने के कारण सात लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि ये सभी जली हुई हालत में केवल कंकाल के रूप में बचे थे, इस कारण उनकी पहचान करना संभव नहीं हो पाया है। हम डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया में हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/रिपेयर, वास्ते मुख्य कारखाना प्रबन्धक, यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिये आनलाईन (ई-टेण्डरिंग) के माध्यम से खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम सं.-01, ई–निविदा सूचना सं. एवं निविदा कार्य का विवरण: टेण्डर नं. "30-जीकेपी-एमडब्लूएस-2025-26-2","रीमूवल/डिस्माउंटिंग ऑफ रोलर बेयरिंग एंड ऐक्सल बॉक्स हाऊसिंग एण्ड क्लीनिंग ऑफ फ्रंट एंड रियर कवर ऑफ आई सी एफ एंड मेमू कोचिंग व्हील इन मेकेनिकल वर्कशाप, गोरखपुर फॉर 1 ईयर", अनुमानित लागत (रू०में): ₹ 15,87,287.52, धरोहर राशि (रू०में): ₹ 31,800/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य: शून्य, निविदा समापन की तिथि एवं अवधि: 08-05-2026, 11:00 बजे, संविदा की अवधि: 12 माह।

• उपरोक्त ई–निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट *http://www.ireps.gov.in* पर देखें।

उप मुख्य यांत्रिक इंजी०/रिपेयर, यां० कार०
मुजाधि/यॉंत्रिक-07 **गोरखपुर**

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

Nagaland State Lotteries
DEAR
VICTORY FRIDAY WEEKLY LOTTERY

Draw No:24 **Price ₹7/-** Draw Date on:17/04/26

1st Prize Amount For Winner ₹ 1 Crore + For Seller ₹ 5 Lakhs/- **59G 47611**

SOLD BY : SELLER - RABEYA BIBI - KADAMBAGACHI & SUB-STOCKIST - ASIRBAD LOTTARY CENTER - DEGANGA

Cons. Prize Amount For Winner ₹ 1000/- + For Seller ₹ 500/- **47611**

(All Remaining Serial & Series of 1st Prize No.)

2nd Prize Amount For Winner ₹ 10,000/- + For Seller ₹ 500/-

11635	17758	23187	27466	36768
49623	50916	66461	67836	76615

3rd Prize Amount For Winner ₹ 500/- + For Seller ₹ 50/-

0872 1881 3672 5085 5113 7230 7834 8375 8684 9482

4th Prize Amount For Winner ₹ 250/- + For Seller ₹ 20/-

0267 1084 2088 2276 3344 5040 5762 5949 6311 8805

5th Prize Amount For Winner ₹ 120/- + For Seller ₹ 10/-

0125	1217	2138	2909	4380	5254	6260	7184	8085	9119
0165	1622	2254	3087	4422	5365	6408	7262	8119	9494
0386	1708	2285	3198	4489	5498	6462	7639	8124	9540
0495	1769	2335	3229	4497	5577	6483	7696	8382	9558
0561	1926	2398	3278	4502	5816	6561	7764	8519	9580
0659	1945	2546	3389	4517	5829	6583	7929	8544	9637
0824	1958	2664	3858	4521	5897	6853	7950	8714	9669
0892	2027	2713	4160	5069	5932	6918	7958	8868	9694
0948	2063	2715	4225	5187	6178	6939	7985	8907	9820
1109	2099	2764	4316	5191	6241	7132	8025	8910	9967

01:00 PM

01:00 PM

Issued by : Director, Nagaland State Lotteries, Kohima
Watch Live Draw On :
nagalandlotteries.com/livedraw

Sikkim State Lotteries
DEAR
CROWN FRIDAY WEEKLY LOTTERY

Draw No:29 **Price ₹7/-** Draw Date on : 17/04/26

1st Prize Amount For Winner ₹ 1 Crore + For Seller ₹ 5 Lakhs/- **96H 88037**

SOLD BY : SELLER - BANI MORAL - NOAPARA & SUB-STOCKIST - BANI AGENCY - MADHABPUR

Cons. Prize Amount For Winner ₹ 1000/- + For Seller ₹ 500/- **88037**

(All Remaining Serial & Series of 1st Prize No.)

2nd Prize Amount For Winner ₹ 10,000/- + For Seller ₹ 500/-

15508	25290	26308	45007	47015
65547	75161	84019	89534	91009

3rd Prize Amount For Winner ₹ 500/- + For Seller ₹ 50/-

1643 2265 2340 3069 3347 5196 5631 5755 8509 8833

4th Prize Amount For Winner ₹ 250/- + For Seller ₹ 20/-

1265 3298 3585 4345 6388 6710 6926 7506 9156 9899

5th Prize Amount For Winner ₹ 120/- + For Seller ₹ 10/-

0292	1182	2458	2899	3667	4475	5275	6226	7608	8780
0329	1305	2461	2983	3842	4558	5418	6228	7735	9078
0559	1328	2492	3116	3907	4611	5491	6428	7951	9331
0609	1564	2555	3156	3922	4827	5666	6514	7973	9356
0613	1772	2655	3171	3974	4997	5790	6578	8033	9357
0774	1855	2680	3221	3975	5075	5915	6594	8116	9401
0810	2005	2720	3273	4128	5104	5983	6841	8212	9567
0892	2225	2729	3425	4142	5119	5997	7051	8469	9594
0910	2349	2822	3429	4244	5164	6128	7097	8520	9606
1173	2406	2874	3534	4349	5203	6157	7396	8635	9723

06:00 PM

06:00 PM

Issued by :The Principal Director, Sikkim State Lotteries, Gangtok
Watch Live Draw On :
sikkimlotteries.com/livedraw

Nagaland State Lotteries
DEAR
HORIZON FRIDAY WEEKLY LOTTERY

Draw No:24 **Price ₹7/-** Draw Date on:17/04/26

1st Prize Amount For Winner ₹ 1 Crore + For Seller ₹ 5 Lakhs/- **40D 50091**

Cons. Prize Amount For Winner ₹ 1000/- + For Seller ₹ 500/- **50091**

(All Remaining Serial & Series of 1st Prize No.)

2nd Prize Amount For Winner ₹ 10,000/- + For Seller ₹ 500/-

03024	05428	07667	27748	34565
35359	55960	76394	90491	99945

3rd Prize Amount For Winner ₹ 500/- + For Seller ₹ 50/-

0210 2317 2665 3294 3755 3844 3966 5291 5692 9179

4th Prize Amount For Winner ₹ 250/- + For Seller ₹ 20/-

0202 1586 1676 2628 4128 4831 5557 5841 6419 7645

5th Prize Amount For Winner ₹ 120/- + For Seller ₹ 10/-

0105	1486	2779	3591	4932	5768	6585	7590	8302	9152
0258	1790	2876	4051	5075	5862	6931	7639	8308	9156
0337	1806	2914	4174	5180	5900	7079	7663	8505	9380
0732	1893	2926	4189	5191	6000	7120	7695	8544	9495
0925	1953	2957	4315	5287	6005	7198	7835	8659	9518
1007	2000	3014	4440	5309	6186	7206	7841	8712	9855
1107	2170	3095	4579	5320	6427	7428	8073	8795	9904
1125	2261	3156	4587	5387	6458	7486	8152	8845	9937
1147	2354	3268	4846	5405	6466	7551	8192	8850	9944
1431	2410	3425	4896	5572	6503	7562	8213	8995	9970

08:00 PM

08:00 PM

Issued by : Director, Nagaland State Lotteries, Kohima
Watch Live Draw On :
nagalandlotteries.com/livedraw

* TDS 2% UNDER SECTION 393(3) IT ACT 2025 SHALL BE DEDUCTED ON SELLERS PRIZE AMOUNT W.E.F. 01.04.2026
PLEASE CHECK THE RESULTS WITH RELEVENT OFFICIAL GOVERNMENT GAZATTE

आसनसोल में केंद्रीय बलों का फ्लैग मार्च, निष्पक्ष चुनाव का भरोसा

आसनसोल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को आसनसोल शहर में केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई और आम नागरिकों को सुरक्षा का संदेश दिया गया।

फ्लैग मार्च की शुरुआत रामधनी मोड़ क्षेत्र से हुई। वहां से केंद्रीय बलों के जवान और स्थानीय पुलिसकर्मी निर्धारित मार्गों से होते हुए बुधा डीएवी स्कूल क्षेत्र तथा आसपास के कई इलाकों से गुजरे। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न सड़कों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

मार्च के दौरान जवानों की अनुशासित टुकड़ियां, आधुनिक सुरक्षा उपकरण और पुलिस वाहनों की मौजूदगी से इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था का संदेश गया। स्थानीय नागरिक अपने घरों और दुकानों के बाहर खड़े होकर फ्लैग मार्च देखते

नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता में विश्वास पैदा करना है, ताकि मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। साथ ही असामाजिक तत्वों और चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों को कड़ा संदेश देना भी इसका हिस्सा है।

फ्लैग मार्च के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं व्यवस्था की निगरानी की। इस अवसर पर एसके हकीम, डीआईजी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ध्रुव दास, डीसी सेंट्रल, तथा अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर रुककर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की।पुलिस सूत्रों ने बताया कि चुनाव को देखते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील बूथों, प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर अतिरिक्त बल तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रवेश मार्गों पर भी जांच अभियान जारी है।

स्थानीय नागरिकों ने कहा कि सुरक्षा बलों की सक्रियता से भरोसा बढ़ा है। कई लोगों का मानना है कि प्रशासन की ऐसी पहल से मतदान के दिन व्यवस्था बेहतर रहेगी और लोग निडर होकर वोट डाल सकेंगे।व्यापारियों ने भी बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी का स्वागत किया। उनका कहना है कि चुनावी समय में शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि दैनिक गतिविधियां प्रभावित न हों।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा, धमकी, अवैध जमावड़ा या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। आने वाले दिनों में आसनसोल तथा आसपास के क्षेत्रों में ऐसे और भी फ्लैग मार्च, नाका जांच और संयुक्त गश्ती अभियान चलाए जाएंगे। प्रशासन मतदान केंद्रों तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। शुक्रवार को निकला केंद्रीय बलों का यह फ्लैग मार्च प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। आसनसोल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही हैं।

जामुड़िया फैक्ट्री में हादसा, श्रमिक की मौत पर भड़के लोग

जामुड़िया। पश्चिम बंगाल के जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र स्थित इकड़ा औद्योगिक इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे ने श्रमिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुपर स्मेल्टर कारखाने में कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के भूरी गांव निवासी सोइबुल काजी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और सहकर्मियों में शोक के साथ भारी आक्रोश फैल गया।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कारखाने में नियमित उत्पादन कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें सोइबुल काजी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कारखाने में कार्यरत अन्य श्रमिकों के बीच भय और नाराजगी का माहौल बन गया। श्रमिक की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में परिजन, स्थानीय लोग और कारखाने के कर्मचारी मुख्य द्वार पर एकत्रित हो गए। इसके बाद कारखाना प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की कमी और लापरवाही के आरोप लगाए। कुछ समय के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

आक्रोशित श्रमिकों और परिजनों का कहना था कि कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों, प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उनका आरोप है कि श्रमिकों से जोखिम भरे वातावरण में काम कराया जाता है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते आवश्यक सावधानियां बरती जातीं तो यह हादसा टाला जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि दुर्घटना में केवल एक श्रमिक ही नहीं, बल्कि कई अन्य कर्मचारी भी घायल हुए हैं। उनका आरोप है कि प्रबंधन पूरे मामले को सीमित रूप में प्रस्तुत कर स्थिति को दबाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर माहौल शांत कराने का प्रयास किया। काफी देर तक समझाइश और वार्ता का दौर चलता रहा। सुरक्षा कारणों से कारखाने के आसपास पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। कारखाना प्रबंधन की ओर से प्रारंभिक प्रतिक्रिया में कहा गया कि हादसा अचानक हुआ और घायल श्रमिक को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि परिजनों को सूचना देने में कुछ विलंब हुआ, लेकिन उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। साथ ही प्रबंधन ने घटना की आंतरिक जांच कराने की बात कही है। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। स्थानीय श्रमिक संगठनों ने भी घटना पर चिंता जताई है और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते औद्योगिक उत्पादन के बीच श्रमिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

दुर्गापुर सभा में शुभेंदु का हमला, भ्रष्टाचार-बेरोजगारी पर घिरी तृणमूल सरकार

दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। इसी क्रम में दुर्गापुर के फुलझड़ मोड़ पर आयोजित भाजपा की चुनावी जनसभा में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बनर्जी के समर्थन में आयोजित इस सभा में उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य में खनन कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वैध खनन घाटों की आड़ में अनेक अवैध घाट संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उनके अनुसार इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी क्षति पहुंच रही है।उन्होंने कहा कि नदियों से अवैध

तरीके से बालू और खनिज निकालने का काम लगातार जारी है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता इस पूरे तंत्र से लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो अवैध खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभा में बेरोजगारी का मुद्दा भी प्रमुख रूप से उठाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दुर्गापुर जैसे औद्योगिक शहर में रोजगार के पर्याप्त अवसर होने चाहिए थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन में विफल रही है। उन्होंने भाजपा की ओर से आश्वासन दिया कि सत्ता परिवर्तन होने पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, बंद पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाएगा तथा युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर की औद्योगिक पहचान को फिर से मजबूत करना भाजपा की प्राथमिकता होगी। अपने भाषण में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम क्षेत्र में वायरल हुए एक कथित वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार की आशंका से घबराकर तृणमूल कांग्रेस विरोधी दलों को प्रभावित करने और राजनीतिक समीकरण बदलने का प्रयास कर रही है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष मामले का विस्तृत उल्लेख नहीं किया।

सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके भाषण के दौरान जोरदार नारेबाजी की और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में उत्साह दिखाया। मंच से शुभेंदु अधिकारी ने मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बनर्जी को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए बदलाव जरूरी है। इस अवसर पर दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण घोरुई सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से घर-घर संपर्क अभियान तेज करने और मतदान दिवस तक सक्रिय रहने का आह्वान किया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दुर्गापुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी और विकास के मुद्दे मतदाताओं पर असर डाल सकते हैं। भाजपा इन्हीं विषयों को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति आगे बढ़ा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस अपने विकास कार्यों और योजनाओं को जनता के सामने रख रही है।फुलझड़ मोड़ पर हुई इस सभा ने स्पष्ट कर दिया कि दुर्गापुर क्षेत्र में चुनावी मुकाबला तेज हो चुका है। आने वाले दिनों में दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और जनसभाओं का दौर और तेज होने की संभावना है।

दुर्गापुर में ममता की पदयात्रा, शक्ति प्रदर्शन से गूंजा शहर

दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने औद्योगिक नगरी दुर्गापुर में विशाल पदयात्रा निकालकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पूरे मार्ग पर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और शहर तृणमूल कांग्रेस के झंडों व नारों से गूंज उठा।

मुख्यमंत्री की पदयात्रा स्टील मार्केट स्थित पांच माथा मोड़ से प्रारंभ हुई और भिंरिगी टी.एन. स्कूल परिसर तक पहुंची। यात्रा का उद्देश्य दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी कवि दत्त तथा दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार के समर्थन में जनसमर्थन जुटाना था। तृणमूल कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को चुनाव प्रचार के महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा।

पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री

ममता बनर्जी ने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास, उद्योग, रोजगार और जनकल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता के सहयोग से यह अभियान और मजबूत होगा। उनके संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया।

यह पदयात्रा नाचन रोड से गुजरते हुए बेनाचिती बाजार क्षेत्र तक पहुंची। मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही एकत्रित हो गए थे। महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक और व्यापारी वर्ग के लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते नजर आए। जैसे ही ममता बनर्जी का काफिला पहुंचा, लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कई स्थानों पर पारंपरिक तरीके से अभिनंदन भी किया गया।

बेनाचिती बाजार क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानदारों ने हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कुछ स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी तृणमूल समर्थकों ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल लगातार निगरानी बनाए हुए था।

तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती सहित कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी भी पदयात्रा में शामिल रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर वातावरण को चुनावी रंग में रंग दिया। जगह-जगह लगाए गए बैनर, पोस्टर और स्वागत द्वारों से पूरा क्षेत्र सजा हुआ दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दुर्गापुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में ममता बनर्जी की यह पदयात्रा चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहां शहरी मतदाता, श्रमिक वर्ग और व्यापारी समुदाय का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में मुख्यमंत्री का सीधे जनता के बीच पहुंचना पार्टी के लिए लाभकारी माना जा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार ने दुर्गापुर क्षेत्र में सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई कार्य किए हैं। इसी आधार पर जनता से फिर समर्थन मांगा जा रहा है। वहीं विपक्ष इस शक्ति प्रदर्शन को केवल चुनावी आयोजन बता रहा है।

आसनसोल दक्षिण में आरोप-प्रत्यारोप तेज, अग्निमित्रा पर लगे कई आरोप

आसनसोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को राजनीतिक माहौल काफी गरम दिखाई दिया। रहमत नगर स्थित तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वार्ड संख्या 82 की पार्षद नरगिस बानो ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक अग्निमित्रा पाल पर क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर भ्रामक जानकारी प्रसारित करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान तृणमूल नेताओं ने दावा किया कि जनता के सामने गलत आंकड़े रखकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है।

पार्षद नरगिस बानो ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व विधायक की ओर से कोई

उल्लेखनीय पहल नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब चुनावी माहौल बनने पर विकास कार्यों की लंबी सूची जारी कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से उस दावे पर आपत्ति जताई, जिसमें वार्ड संख्या 82 में 49 सोलर लाइट लगाए जाने की बात कही गई थी। पार्षद ने इसे पूरी तरह तथ्यहीन बताते हुए कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार का कोई कार्य उनके संज्ञान में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रहमत नगर, आसपास की गलियों, जलनिकासी व्यवस्था, सड़क मरम्मत, पेयजल सुविधा और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था जैसे कई कार्य राज्य सरकार की योजनाओं से पूरे किए गए हैं। पार्षद के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विकासोन्मुख नीतियों के कारण ही क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय स्तर पर भी जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देकर समाधान कराया जा रहा है। नरगिस बानो ने आगे कहा कि वार्ड संख्या 82 में लोगों की मांग के अनुसार सड़क सुधार, नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट मरम्मत तथा सामाजिक सहायता योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस जनता के बीच रहकर काम करती है, जबकि विरोधी दल केवल आरोप लगाने तक सीमित हैं। उनके अनुसार जनता वास्तविक विकास और कागजी दावों का अंतर अच्छी तरह समझती है। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पूर्व पार्षद सोहराब अली ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अग्निमित्रा पाल विधायक थीं, तब क्षेत्र में अपेक्षित गति से विकास नहीं हुआ। कई योजनाएं अधूरी रहीं और स्थानीय समस्याएं जस की तस बनी रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय लोगों को बार-बार शिकायतें करनी पड़ती थीं, लेकिन समाधान नहीं मिलता था। सोहराब अली ने कहा कि पूर्व विधायक तापस बंदोपाध्याय के कार्यकाल में अनेक आधारभूत विकास योजनाओं की शुरुआत हुई थी। सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार और नागरिक सेवाओं में सुधार उसी अवधि में गति पकड़ सका था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान समय में उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए नए कार्य भी किए जा रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर शुक्रवार शाम तक भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है।

आसनसोल में पुलिस रेड, चुनाव से पहले सुरक्षा घेरा कड़ा

आसनसोल। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार रात व्यापक सुरक्षा अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र में अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस आयुक्त डॉ. प्रणव कुमार के निर्देशन में यह विशेष 'नाइट रेड' अभियान देर रात 10 बजे से तड़के 2 बजे तक कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ संचालित किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य चुनाव पूर्व शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करना था। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभियान में बड़ी संख्या में अधिकारी, थाना प्रभारी, विशेष बल और गश्ती दल शामिल किए गए थे। सभी संवेदनशील इलाकों, बाजार क्षेत्रों, परिवहन मार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों और पुराने आपराधिक

गतिविधियों वाले स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई। पुलिस टीमों ने संदिग्ध लोगों की पहचान, फरार आरोपियों की तलाश और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न आपराधिक मामलों में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई चल रही थी। इसके अतिरिक्त कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए 276 व्यक्तियों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। इन सभी लोगों से पूछताछ कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। पुलिस को फरार अपराधियों के विरुद्ध भी उल्लेखनीय सफलता मिली। लंबे समय से लंबित मामलों में कार्रवाई करते हुए 46 गैर-जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध कारोबार पर भी कड़ा प्रहार किया। विभिन्न स्थानों से 6 लाख 66 हजार रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की गई। इस राशि के संबंध में संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही 157 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई, जिसे अवैध रूप से संग्रहित और बिक्री के लिए रखा गया था।

कोयला घोटाले में ईडी सख्त, 482 करोड़ की संपत्ति कुर्क

आसनसोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल-रानीगंज कोयला क्षेत्र में वर्ष 2015 से कथित रूप से जारी अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी का मामला अब देश के बड़े आर्थिक घोटालों में शामिल माना जा रहा है। इस बहुचर्चित मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। शुक्रवार को सामने आई जानकारी के अनुसार ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 159.51 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इसके साथ ही अब तक जब्त की गई कुल संपत्तियों का मूल्य बढ़कर 482.22 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

जांच एजेंसियों के अनुसार यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल के कोल बेल्ट क्षेत्र में अवैध खनन, सरकारी खदानों से कोयले की चोरी और अवैध परिवहन से जुड़ा है। आरोप है कि वर्षों तक संगठित तरीके से कोयले की निकासी कर उसे बाजार में बेचा गया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ। अधिकारियों का अनुमान है कि इस घोटाले से सरकार को लगभग 1340 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है। ईडी की जांच में सामने आया है कि कुछ निजी कंपनियों ने कथित रूप से अवैध रूप से निकाले गए कोयले की खरीद नकद भुगतान के माध्यम से की। इससे अवैध कमाई को वैध कारोबार के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। एजेंसी का दावा है कि इस धनराशि को बाद में विभिन्न निवेश माध्यमों और वित्तीय साधनों में लगाया गया।

कुर्क की गई संपत्तियों में कॉर्पोरेट बॉन्ड, निवेश फंड और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं। इनमें श्याम स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड से जुड़े निवेशों का भी उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये कंपनियां श्याम समूह से संबंधित हैं और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की जा रही है। मामले की जांच में मुख्य आरोपी के रूप में अनूप माजी उर्फ 'लाला' का नाम सामने आया है। ईडी के अनुसार कथित सिंडिकेट उसके नेतृत्व में संचालित होता था। आरोप है कि यह नेटवर्क ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टा क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी तथा अवैध खुदाई में शामिल था। एजेंसियों का कहना है कि यह गतिविधि लंबे समय तक संगठित ढंग से चलाई गई।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अवैध कोयले के परिवहन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। कथित रूप से ÷लाला पैड÷ नामक नकली परिवहन चालान तैयार किए जाते थे, जिन पर अस्तित्वहीन कंपनियों के नाम अंकित रहते थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ट्रकों को विभिन्न मार्गों से गुजराया जाता था।सूत्रों के अनुसार ट्रक चालकों को पहचान संकेत के तौर पर छोटे मूल्य के नोट दिए जाते थे, जिनका उपयोग कोड के रूप में किया जाता था।

आसनसोल में दिखा शत्रुघ्न सिन्हा का लापता पोस्टर

आसनसोल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर राज्य की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिम बर्दवान जिले की नौ महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है और चुनाव प्रचार के समापन में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे समय में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस सांसद एवं अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की प्रचार अभियान से दूरी चर्चा का विषय बन गई है। शुक्रवार को आसनसोल शहर के कई हिस्सों में उनके खिलाफ पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया।

शहर में लगाए गए पोस्टरों में सांसद को 'लापता' बताते हुए तीखे सवाल उठाए गए हैं। कुछ पोस्टरों पर 'शेम' तथा 'विकास कहाँ है?' जैसे नारे लिखे गए, जिनके माध्यम से क्षेत्रीय विकास और जनप्रतिनिधि की सक्रियता पर सवाल खड़े किए

गए। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

गौरतलब है कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए प्रमुख चेहरों में शामिल किया है। पार्टी उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में प्रस्तुत करती रही है, लेकिन हाल के दिनों में वे सार्वजनिक चुनावी कार्यक्रमों में नजर नहीं आए हैं। इसी कारण विरोधी दलों को सरकार और पार्टी पर निशाना साधने का अवसर मिल गया है।

स्थानीय राजनीतिक सूत्रों के अनुसार सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आखिरी बार 23 मार्च को जामुड़िया क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी हरे राम सिंह के समर्थन में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाई दिए थे। उस कार्यक्रम के दौरान उनकी गाड़ी पर नीली बत्ती लगे होने को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। इसके बाद से वे किसी बड़े चुनावी मंच या जनसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दुर्गापुर, पांडेश्वर, आसनसोल और बाराबनी जैसे क्षेत्रों में लगातार सभाएं कर चुके हैं। इसके बावजूद इन कार्यक्रमों में सांसद की अनुपस्थिति ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जिज्ञासा और असंतोष दोनों बढ़ा दिए हैं। कई कार्यकर्ता अनौपचारिक बातचीत में यह सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव निर्णायक मोड़ पर है, तब क्षेत्रीय सांसद मैदान में सक्रिय क्यों नहीं हैं।

दूसरी ओर बर्दवान-दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वे प्रेस वार्ताओं, जनसंपर्क अभियानों और विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। इससे तुलना का माहौल भी बन रहा है और राजनीतिक चर्चाओं में यह विषय प्रमुखता से उठ रहा है।

आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सात विधानसभा सीटें आती हैं। वर्ष 2021 के चुनाव में आसनसोल दक्षिण और कुल्टी सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस बार तृणमूल कांग्रेस के लिए यह क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। चुनावी समीकरणों को देखते हुए पार्टी के बड़े नेताओं की सक्रियता जरूरी मानी जा रही है।

विपक्षी दलों ने पोस्टर प्रकरण को मुद्दा बनाते हुए तृणमूल कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। उनका कहना है कि जनता विकास कार्यों और जनप्रतिनिधियों की उपलब्धता को लेकर जवाब चाहती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

संक्षिप्त समाचार

9 साल टीचिंग करने वाली अपूर्वा बनी मिसेज इंडिया 2026

आरा (भोजपुर), एजेंसी। '2023 में मैं पहली बार मां बनी, तो ऐसा लगा कि लाइफ थम गई है, क्योंकि मेरी पहली प्रॉयरिटी बेटी थी। ये हर मां के साथ होता है। मैं बेटी के साथ खुश थी। लेकिन करियर को लेकर डिप्रेशन में चली गई। मिसेज बिहार का टाइटल जीतने के बाद मैं अपने परिवार में खुश थी, लेकिन जब मिसेज इंडिया के बारे में पता चला, तो मेरे परिवार ने जबरन मुझसे रजिस्ट्रेशन कराया और नतीजा आपके सामने है।' आरा शहर के पुरानी पुलिस लाइन की रहने वाली 30 साल की डॉ. अपूर्वा वर्मा ने ये बातें कही। दरअसल, अपूर्वा वर्मा ने नेशनल लेवल पर मिसेज इंडिया का अवार्ड जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में 11 अप्रैल को देश के अलग-अलग राज्यों की 22 प्रतिभागियों को पछाड़ कर अपूर्वा ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। अपूर्वा के पिता विजय लाल पेशे से कारोबारी हैं, जबकि मां सरोज श्रीवास्तव हाउस वाइफ हैं। अपूर्वा के पति अरुंजय वर्मा पटना के गांधी मैदान स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (हेड ऑफिस) में मैनेजर के पद पर हैं।

पटना से दिल्ली तक बदला पता; नीतीश कुमार बने नितिन नवीन के पड़ोसी, 9 नंबर आवास में रहेंगे

पटना, एजेंसी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें अब देशभर में जेड प्लस (+) श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में उनके लिए सरकारी आवास भी आवंटित कर दिया गया है। वे पटना में 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहेंगे, जबकि दिल्ली में उन्हें सुनहरी बाग रोड पर टाइप-8 श्रेणी का 9 नंबर बंगला मिला है। जानकारी के अनुसार, इस श्रेणी के बंगले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी निवास करते हैं। नीतीश कुमार अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितनि नवीन के पड़ोसी बन जाएंगे। वे 8 नंबर बंगले में रहते हैं। नीतीश कुमार को आवंटित आवास करीब तीन एकड़ में फैला हुआ है और इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। बंगले में पांच बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और स्टडी रूम के अलावा छह स्टाफ क्वार्टर भी हैं। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। उधर, पटना में पूर्व मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग से उनका अधिकांश सामान 7 सर्कुलर रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट कर दिया गया है। यह आवास 10 सर्कुलर रोड के नजदीक है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार रहता है।

इधर 14 अप्रैल को इस्तीफे के बाद से नीतीश कुमार बाहर नहीं निकले हैं। करीब 36 घंटे से अधिक समय से वे आवास में ही हैं। बताया जाता है कि जल्द ही वे 7 सर्कुलर रोड आवास में शफ्टि हो जाएंगे।

डॉक्टर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का आरजेडी विधायक पर आरोप

सिवान, एजेंसी। बिहार के सिवान जिले के महादेवा थाना क्षेत्र स्थित झुनापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया है. इस मामले में रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पर एफआईआर दर्ज हुआ है. ओसामा शहाब के साथ ही साबिर मियां और फरहान मियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरजेडी विधायक ओसामा शहाब पर एफआईआर : जानकारी के अनुसार, डॉ. सुधा सिंह और उनके परिवार ने झुनापुर स्थित एक जमीन (खाता नंबर 82, सर्वे नंबर 941, रकबा 11.904 डिसमिल) पर अपना दावा किया है. डॉ. सिंह के अनुसार, जब वे उक्त जमीन पर निर्माण कार्य करा रही थीं, तभी ओसामा शहाब द्वारा फोन कर जमीन पर अपना भी बैनामा होने की बात कही गई और कागजात दिखाने को कहा गया. डॉ. सुधा सिंह ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने अपने सभी कागजात प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन इसके बाद संपर्क नहीं हो सका. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे दोबारा निर्माण कार्य करा रही थीं, तभी ओसामा शहाब ने फोन कर काम रुकवाने को कहा. इस घटना को लेकर डॉ. सुधा सिंह ने महादेवा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने ओसामा शहाब, साबिर मियां और फरहान मियां को नामजद आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है।

बिहार में डिजिटल जनगणना, घर बैठे खुद भरें अपना ब्योरा

देना होगा इन 33 सवालों का जवाब

पटना, एजेंसी। बिहार में जनगणना 2027 की शुरुआत 17 अप्रैल 2026 से होने जा रही है. पहले चरण में राज्य के लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका मिला है. यह स्व-गणना प्रक्रिया 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलेगी. लोग घर बैठे जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेंगे.

डिजिटल जनगणना आज से शुरू : स्व-गणना करने की अंतिम तिथि 1 मई रात 12 बजे तक है. 17 अप्रैल यानी शुक्रवार से एक मई तक बिहारवासी अपनी गणना मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. इस दौरान लोग आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन करके खुद अपने परिवार और घर से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं.

जनगणना को सफल बनाने की तैयारी पूरी: राजधानी पटना में आगामी जनगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में पटना के प्रधान जनगणना अधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने समाहरणालय परिसर में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विस्तृत जानकारी साझा की.

मकानों की गिनती में जियो-रेफरेंसिंग तकनीक : पहले चरण में मकानों की गणना 2 से 31 मई तक होगी. इसके लिए प्रगणकों को मकान का सूचीकरण करने, डिजिटल मोड में काम करने समेत अन्य तकनीकी जानकारी दी गई है. उन्हें मकानों की गणना फॉर्म भरने की विधि व आधुनिक तकनीक के उपयोग के बारे में बताया गया.

स्व-गणना क्या है और इसके फायदे: नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपना और अपने परिवार का डिटेल भर सकते हैं. इसमें प्रगणक के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ता है और त्रुटियां कम होती हैं. स्व-गणना से समय की बचत होती है. डेटा कलेक्शन को आधुनिक बनाता है और समय की बचत होती है.

वो 33 सवाल, जो आप से पूछे जाएंगे : भारत की जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना की प्रक्रिया में 33 सवाल पूछे जाएंगे. ये सारी जानकारी 17 अप्रैल से ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल में भरी जा सकेगी. बाद में 2 मई से इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा. जो कॉलम भरने हैं उनमें ये सवाल रहेंगे- भवन संख्या, घर/मकान संख्या, मकान के फर्श में उपयोग की गई प्रमुख सामग्री, मकान की दीवारों में उपयोग की गई प्रमुख सामग्री, मकान की छत में इस्तेमाल की गई प्रमुख सामग्री.

घर की इनकम से लेकर पढ़ाई तक : मकान का उपयोग (व्यावसायिक, आवासीय आदि), मकान की स्थिति (अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण-शीर्ण), परिवार संख्या (हाउसहोल्ड नंबर), परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, परिवार के मुखिया की सामाजित स्थिति, मकान के स्वामित्व की स्थिति, घर में रहने वाले कमरों की संख्या, परिवार में विवाहित जोड़ों की संख्या, पीने के पानी का मुख्य स्रोत, पीने के पानी की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार और उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत (बिजली, केरोसिन, आदि).

प्रगणकों को दी जा रही ट्रेनिंग: पटना जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एन ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों और नगर निकायों में चयनित प्रगणकों (एन्यूमरेटर) और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य तेजी से चल रहा है. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है, ताकि सभी कर्मियों को जनगणना से जुड़ी प्रक्रियाओं, तकनीकी पहलुओं और जिम्मेदारियों की पूरी जानकारी मिल सके.

गोपनीय रखी जाएंगी सारी जानकारी: इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और उनका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण के लिए ही किया जाएगा.

मसौढ़ी में ट्रेनिंग जारी: इसके प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना है. मसौढ़ी में गुरुवार से प्रखंड के प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की प्रशिक्षण शुरूआत हो गई है. चार्ज पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय गिरजा कुंवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया है.

प्रशिक्षण के अंतिम दिन ऑनलाइन मोबाइल, ऐप डेटा प्रविष्टि, मकान का सूचिकरण, गणना व नजरी नक्शा बनाने की जानकारी दी जाएगी. बीडीओ प्रभाकर ने प्रगणकों को कहा कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्षेत्र के जनसंख्या का आकलन, संबंधित क्षेत्रों का सीमांकन व डिजिटल मैपिंग का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बीएड विभाग की मनमानी, अंकतालिका के नाम पर खाली लिफाफा, छात्रों से अवैध वसूली का आरोप

मेरठ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) की आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचते ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) के गोपनीय विभाग में बीएड खिड़की पर मारामारी मच गई है। अंकतालिका (मार्कशीट) पाने के लिए छात्र महीनों से विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अव्यवस्था इस कदर है कि कई महीने पहले आवेदन करने वाले छात्रों को मार्कशीट के नाम पर खाली लिफाफे भेजे जा रहे हैं।

ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला गाजियाबाद निवासी छात्र कृष्ण कुमार का सामने आया है। कृष्ण कुमार ने आगामी टीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए 21 जनवरी को छात्र सहायता केंद्र से अंकतालिका के लिए आवेदन किया था। तीन महीने बीत जाने के बाद विश्वविद्यालय ने उनके पते पर डाक भेजी, लेकिन लिफाफा पूरी तरह खाली निकला। इस बड़ी लापरवाही पर पीड़ित छात्र जब बृहस्पतिवार सुबह कैंपस पहुंचा तो अधिकारियों ने राहत देने की बजाय उसे फिर से आवेदन की प्रक्रिया दोहराने को कह दिया। दिनभर विभाग की चौखट पर भटकने के बाद छात्र ने अपनी व्यथा छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अंकित अधाना को सुनाई। अंकित अधाना ने तुरंत मामले में हस्तक्षेप किया और परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार मौर्य को पूरी स्थिति से अवगत कराया। इसके बावजूद विभागीय कर्मचारियों ने घंटों छात्र को इधर-उधर टहलाकर परेशान किया। अंत में जब पूर्व महामंत्री अंकित अधाना ने कुलपति से शिकायत करने और हंगामे की चेतावनी दी, तब कहीं जाकर शाम को छात्र को उसकी अंकतालिका मिल सकी। अंकित अधाना का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को बेवजह परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लिफाफे जानबूझकर खाली भेजे जा रहे हैं ताकि छात्रों को परेशान करके अवैध वसूली की जा सके।

लखनऊ से आई टीम की मेरठ में बड़ी कार्रवाई, 2800 किलो पनीर जब्त; गड्ढा खोदकर जमीन में दबाया

मेरठ, एजेंसी। जानीखुर्द के नंगला कुंभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग (लखनऊ टीम) द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई ने मिलावटखोरों में हड़कंप मचा दिया है। बृहस्पतिवार शाम को छापा मारकर करीब 28 कुंतल मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। नंगला कुंभा क्षेत्र में लंबे समय से मिलावटी पनीर और मावा बनाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग को अवगत कराया था कि क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर अवैध रूप से मिलावटी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। पूर्व में विभाग द्वारा सैंपल लेकर खानापूर्ति करने की शिकायतों के बाद, ग्रामीणों ने सीधे मुख्यमंत्री और लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग से गुहार लगाई थी।

लखनऊ टीम का गोपनीय अभियान

ग्रामीणों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ से आई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोपनीयता बरतते हुए यह कार्रवाई की। टीम ने मेरठ के स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मियों को भी इसकी सूचना नहीं दी थी। टीम ने नंगला कुंभा में पनीर बनाने वाली भट्ठियों का औचक निरीक्षण किया और अलग-अलग दो स्थानों से पनीर के नमूने जांच के लिए एकत्र किए।

28 कुंतल मिलावटी पनीर नष्ट : जांच के दौरान पनीर में मिलावट की पुष्टि होने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 28 कुंतल मिलावटी पनीर जब्त किया। मौके पर ही गड्ढा खुदवाकर सारा जब्त किया गया पनीर नष्ट करवा दिया, ताकि यह दोबारा इस्तेमाल न हो सके।

संचालकों में हड़कंप, कई फरार : इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई की भनक लगते ही कई पनीर संचालक अपने संस्थानों को बंद करके मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान टीम को हल्का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन विभाग ने अपनी कार्रवाई जारी रखी।

भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई : खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। टीम के सदस्य बीके राठी ने बताया कि वे अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपेंगे। इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में खौफ का माहौल है और उम्मीद है कि इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

नौ वर्षों में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती : मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में वर्ष 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि नौ साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे।

उन्होंने बताया कि बीते नौ वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि 2017 के पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय मे 3 हजार से अधिक नहीं थी। वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60 हजार पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग करवाई जाती है।

रिटायर्ड फौजी की क्रूरता, नाबालिग बेटे का सीना कर दिया था छलनी; फिर फूट-फूटकर रोया; उम्रकैद की मिली सजा

आगरा, एजेंसी। आगरा में गोली मारकर बेटे की हत्या करने के मामले में करीब 19 महीने बाद अदालत ने पिता धीरज को दोषी माना। एडीजे मृदुल दुबे ने उसे उम्रकैद के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में हत्या की चश्मदीद गवाह आरोपी की पत्नी और छोटा बेटा था, जिनकी गवाही अहम रही।

थाना सदर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, थाना बासोनी क्षेत्र के गांव बांगरपुर निवासी मुकेश ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बहन सुधा की शादी उखर्रा रोड रामजी विहार कॉलोनी निवासी धीरज के साथ की थी। शादी के दौरान धीरज सेना में कार्यरत था। शराब पीने की लत की वजह से इस्तीफा देकर घर आ गया।

आरोप है कि वह घर पर भी अक्सर नशे में रहता था। बहन इसका विरोध करती थी। आरोपी के दो बेटे 14 वर्षीय विवेक और 11 वर्षीय नितिन थे। 21 अगस्त, 2024 को शाम 4 बजे आरोपी नशे में घर आया और विवेक से गालीगलौज करने लगा। बहन ने बेटे को भैंस के लिए सानी लगाने भेज दिया। वह भूसा में पानी डाल रहा था तभी आरोपी ने छत से दुनाली बंदूक से उस पर गोली चला दी। बच जाने पर नीचे आकर लाइसेंसी पिस्टल से विवेक के सीने में गोली मार दी। पुलिस ने 23 अगस्त, 2024 को उसे अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया था। मामले में आरोपी की पत्नी सुधा, आरोपी के छोटे बेटे नितिन की गवाही अहम मानी गई।

धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत झूठे मामलों पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

लखनऊ, एजेंसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत झूठे मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की जानकारी देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि कई मामलों में तीसरे पक्ष द्वारा बिना ठोस आधार के एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, जो बाद में निराधार साबित होती हैं। इससे जांच एजेंसियों का समय और संसाधन व्यर्थ हो रहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार बताए कि ऐसी झूठी एफआईआर के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें बहराइच में तीन मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कथित पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से संबंध में है।

क्या सम्राट चौधरी बिहार में चालू करेंगे शराब :अनंत सिंह

पटना, एजेंसी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी को लेकर बहस छिड़ गई है. कभी नीतीश के इस फैसले में उनके साथ रहने वाले नेता ही अब शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं. इसी कड़ी में मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बिहार में फिर से शराब चालू करने की मांग की है। 'बिहार में चालू हो शराब'- अनंत सिंहः अनंत सिंह ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शुक्रवार (17 अप्रैल) को मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर कहा कि हम कहते हैं कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए. मैं भी पक्ष में था कि बिहार में शराब बंद हो. लेकिन बंद होने से दारू पीने वाला पी ही रहा है.अनंत सिंह ने सम्राट चौधरी से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी और मोकामा क्षेत्र में अस्पताल बनाने की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अब आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा. ये चुनाव मेरा आखिरी था. आप (सम्राट चौधरी) एक हॉस्पिटल बढ़िया बना दीजिए. अस्पताल बनने से सबको आराम होगा, नहीं तो मरीज को पटना आना पड़ता है. सब सक्षम नहीं होता है. पटना आने में काफी खर्च होता है.अनंत सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी ने अस्पताल बनाने का आश्वासन दिया है. निशांत कुमार के राजनीति में आने और डिप्टी सीएम बनने से इनकार करने पर अनंत सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा थी. उन्होंने कहा कि हम नहीं बनेंगे. उनकी जो इच्छा थी वह किया.

बिहार में फर्जीवाड़ा गिरोह पर एक्शनः एडीईओ परीक्षा में 20 लाख की डील का भंडाफोड़

मुंगेर, एजेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा 14 व 15 अप्रैल को आयोजित सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (एडीईओ) परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़ा गिरोह का खुलासा हुआ है। परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 15 से 20 लाख रुपये तक की वसूली की जा रही थी। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में मास्टरमाइंड, तीन लाइनर और 18 अभ्यर्थियों समेत कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड सूजल कुमार (भगतचौकी), लाइनर समीर कुमार (पटना), प्रियांशू कुमार (धरहरा) और प्रशांत कुमार (कहलगांव, भागलपुर) शामिल हैं। सभी लाइनरों को होटल से तथा मास्टरमाइंड को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पाए गए हैं। यह गिरोह कई जिलों में सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस ग्रुप की गहन जांच कर बड़े सरगना तक पहुंचने में जुटी है।

पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के अनुसार, मास्टरमाइंड सूजल अपने अधीन तीन लाइनरों के जरिए पूरे नेटवर्क का संचालन करता था। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर से मिलीभगत कर प्रश्नपत्र की तस्वीर मोबाइल से खींचकर मास्टरमाइंड को भेजी जाती थी। इसके बाद हल प्रश्नपत्र वापस लाइनर के पास पहुंचता, जो अभ्यर्थियों को उत्तर भरने में मदद करता था। गिरफ्तार लाइनरों के पास से छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप भी बरामद किए गए हैं, जिनमें प्रश्नपत्र और उसके उत्तर सुरक्षित पाए गए हैं।

जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार सभी 18 अभ्यर्थियों ने एक ही कोचिंग सेंटर के माध्यम से इस गिरोह से संपर्क किया था। पुलिस ने कोचिंग सेंटर की पहचान कर ली है और उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उपेन्द्र ट्रेनिंग स्कूल परीक्षा केंद्र की केंद्राधीक्षक अर्चना कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने बायोमेट्रिक ऑपरेटर को एंड्रॉयड मोबाइल उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे फर्जीवाड़ा संभव हो सका।

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप ग्रुप में बिहार के कई जिलों के संदिग्धों और सैकड़ों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही बड़े खुलासे की संभावना है।

10% का इजाफा हुआ फ्रेंच ओपन की इनामी राशि में

7 करोड़ 21 लाख डॉलर मिलेंगे फ्रेंच ओपन विजेता को

नई दिल्ली, एजेंसी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की इनामी राशि में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिससे कुल इनामी राशि छह करोड़ 17 लाख यूरो (सात करोड़ 21 लाख डॉलर) हो गई है। यह कुल राशि पिछले साल के मुकाबले 53 लाख यूरो अधिक है। प्रतियोगिता 24 मई को पश्चिमी पेरिस के रोलां गैरो में शुरू होगी।पुरुष और महिला एकल चैंपियन को 28 लाख यूरो और उप विजेता को 14 लाख यूरो मिलेंगे। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को सात लाख 50 हजार यूरो और पहले दौरे में हारने वाले खिलाड़ियों को 87 हजार यूरो मिलेंगे। पुरुष और महिला युगल के विजेताओं को छह लाख यूरो और मिश्रित युगल की चैंपियन जोड़ी को एक लाख 22 हजार यूरो मिलेंगे। पिछले साल कार्लोस अल्कारेज ने पांच सेट के तक चले फाइनल में यानिक सिनर को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता था जबकि कोको गॉफ ने एरिना सबालेंका को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया था।

मेसी कानूनी विवाद में फंसे, दिग्गज फुटबॉलर ने पूरी नहीं की ये शर्त

ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं। मियामी की इवेंट कंपनी वीआईडी म्यूजिक ग्रुप ने मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मामला पिछले साल अक्तूबर में मियामी के हॉर्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए अर्जेंटीना बनाम वेनेजुएला दोस्ताना मैच से जुड़ा है। कंपनी का आरोप है कि मेसी ने इस मैच में खेलने के लिए किए गए लगभग सात मिलियन डॉलर के अनुबंध का उल्लंघन किया। समझौते के तहत उन्हें कम से कम 30 मिनट मैदान पर उतरना था, जब तक कि वे चोटिल न हों। हालांकि, मेसी ने मैच में हिस्सा नहीं लिया और स्टेडियम के एक लग्जरी सुइट से मुकाबला देखा।

भारी आर्थिक नुकसान का दावा

कंपनी का दावा है कि उनकी अनुपस्थिति से टिकट बिक्री, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ा जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। वीआईडी म्यूजिक ग्रुप के वकील राल्फ पैटिनो के अनुसार, मेसी की भागीदारी इस डील की एक अहम शर्त थी और यह सीधे तौर पर मैच की व्यावसायिक सफलता से जुड़ी हुई थी। कंपनी ने अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के साथ वेनेजुएला और प्यूर्टो रिको के खिलाफ दो मैत्री मैचों के प्रमोशन का करार किया था। दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला के खिलाफ मैच में नहीं खेलने के बावजूद मेसी अगले ही दिन मेजर लीग सॉकर में अपनी टीम इंटर मियामी सीएफ के लिए उतरे और अटलांटा के खिलाफ 4-0 की जीत में दो गोल दागे और प्यूर्टो रिको के खिलाफ खेले गए दूसरे दोस्ताना मैच में हिस्सा लिया।

रोहित की चोट गंभीर नहीं: कोच जयवर्धने

मुंबई, एजेंसी। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत उम्मीद के अनुरूप नहीं रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद टीम को लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। टीम के लिए चिंता की बात यह भी है कि उसके स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा चोटिल हो गए हैं और वह पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर रहे थे।

आरसीबी के खिलाफ चोटिल हुए थे

पंजाब के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से हुआ था। इस मैच में हिटमैन दूसरी पारी के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझते नजर आए थे और रन-चेज के छठे ओवर में ही उन्हें चोट के कारण अपनी पारी बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बताया था कि पंजाब के खिलाफ रोहित को आराम दिया गया है। उनकी वापसी फिलहाल निश्चित नहीं है। हार्दिक ने कहा था, उन्हें यह देखने में कुछ मैच लगेंगे कि वह फिलहाल किस स्थिति में हैं।

रोहित पर दबाव नहीं डालना चाहता टीम प्रबंधन

अब टीम के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने भी रोहित की फिटनेस पर अपडेट दिया है। मुख्य कोच ने कहा कि रोहित शर्मा की चोट गंभीर नहीं है और टीम प्रबंधन उन्हें ज्यादा दबाव में नहीं रखना चाहता क्योंकि टूर्नामेंट अभी शुरुआती दौर में है। जयवर्धने ने कहा, रोहित ने बुधवार से दौड़ना शुरू कर दिया है, बल्लेबाजी भी की है। हम हर दिन उनकी प्रगति का आकलन कर रहे हैं। उनकी चोट गंभीर नहीं है लेकिन साथ ही, हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते और अभी सत्र की शुरुआत है। जयवर्धने ने इस बात को नकार दिया की टीम की लगातार चौथी हार से कप्तान हार्दिक पांड्या दबाव में हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ हार्दिक की जिम्मेदारी है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है। जब हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, बल्कि यह पता करना मेरी और टीम प्रबंधन में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि हम बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं।

वीर चोटरानी हैम्बर्ग स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, अभय-रमित और जोशना हुए बाहर

नई दिल्ली। वीर चोटरानी ने पुरुषों के दूसरे राउंड में जर्मनी के आठवें सीड राफेल कंदरा को 3-0 से हराकर हैम्बर्ग ओपन स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। यह पीएसए कांस्य पदक स्तर का इवेंट है। इस भारतीय खिलाड़ी ने शुरू से आखिर तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्हें 11-8, 11-7, 11-7 से जीत हासिल करने और आखिरी आठ में पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगे। चोटरानी ने कंदरा को सीधे गेम में हराकर बड़ा उलटफेर किया। हालांकि, चोटरानी के हमवतन और पांचवें वरीयता प्राप्त अभय सिंह और सातवें वरीय रमित टंडन दूसरे राउंड में बाहर हो गए। सिंह इंग्लैंड के सैम टॉड से 9-11, 11-7, 4-11, 2-11 हारे। टंडन को हंगरी के बालाज फार्कास ने 10-12, 11-4, 5-11, 9-11 से हराया। सैम टॉड ने सिंह को हराने के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। टॉड ने कहा, मुझे पता है कि अभय हाल ही में अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि एल गौना में उसके कुछ अच्छे परिणाम आए थे और उसने इंडियन ओपन जीता था। मुझे पता था कि आज का मैच मुश्किल होगा और मैंने उसके साथ पोंटेफ्रैक्ट में जो मेरा क्लब है कुछ बार ट्रेनिंग की है, इसलिए मैं उसका गेम अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि हम कुछ बार साथ में खेले हैं।

महिलाओं के वर्ग में पूर्व महिला विश्व की 10वें नंबर की खिलाड़ी जोशना चिनप्पा को आठवीं वरीयता प्राप्त जोएल किंग ने हराया। किंग ने 11-9, 11-7, 9-11, 11-4 से जीत हासिल की। स्पेन की मार्टा डोमिनगेज भी नंबर 6 सीड मैलिफ को हराने के बाद पहली बार कांस्य पदक के आखिरी आठ में खेलेंगी। डोमिनगेज ने लगातार छह हार का सिलसिला खत्म करते हुए 11-7, 9-11, 11-5, 11-3 से जीत हासिल करके अपने पहले क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई।

'टीम इंडिया में जल्द दिखेगा जलवा', वैभव की फैन हुई शेफाली

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट में उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मशहूर एंकर शेफाली बग्गा ने उनके प्रदर्शन की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि वह जल्द ही भारत की टी20 टीम में जगह बना सकते हैं। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव ने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है और अब उन्हें टीम इंडिया के संभावित खिलाड़ियों में देखा जा रहा है।

आत्मविश्वास बनाता है खास'

शेफाली बग्गा ने वैभव की बल्लेबाजी शैली की तारीफ करते हुए कहा, 'वह बहुत क्लास के साथ खेलते हैं और गेंदबाजों पर हावी रहते हैं। हमने पिछले साल देखा कि उन्होंने शतक बनाकर सभी को प्रभावित किया।' उन्होंने यह भी बताया कि इतनी कम उम्र में जिस तरह वैभव बड़े गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, वह उनकी खासियत को दर्शाता है।

आईपीएल तक का शानदार सफर

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अंडर-19 स्तर पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई।

डियर साप्ताहिक लॉटरी जलपाईगुड़ी निवासी ने ₹1 करोड़ जीते

जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से श्री कल्याण तांतरा ने **31.01.2026** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर ₹1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **9 8 D 10366** है। उन्होंने सिक्किम स्टेट लॉटरीज के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। "हर किसी के सपने पूरे करना एक अत्यंत कठिन कार्य होगा, क्योंकि अधिकतर मध्यमवर्गीय लोगों की आय सीमित संसाधनों के इर्द-गिर्द घूमती है। डियर लॉटरी के माध्यम से अपनी किस्मत आजमाना एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि हम केवल कुछ रुपए के खर्च द्वारा ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने जानने वालों को डियर टिकटों के माध्यम से अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दूंगा," विजेता ने कहा।

*विजेता का विवरण सरकारी वेबसाइट से लिया गया है।

पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2026

टिकट मूल्य MRP ₹500

प्रथम पुरस्कार विजेता के लिए राशि ₹6 करोड़ गारंटीड

ड्रॉ दिनांक 18.04.2026 6PM Onwards

Seller Prize Amount: ₹30 LAKHS

प्रथम पुरस्कार केवल बिक्री की गयी टिकटों में से ही निकाली जायेगी।

Sub-Stockist Prize Amount: ₹10 LAKHS

द्वितीय पुरस्कार राशि विजेताओं के लिए ₹50 लाख

Seller Prize Amount: ₹ 5 Lakhs
Sub-Stockist Prize Amount: ₹ 2 Lakhs

तृतीय पुरस्कार राशि विजेताओं के लिए ₹25 लाख

Seller Prize Amount: ₹ 2 Lakhs
Sub-Stockist Prize Amount: ₹ 1 Lakhs

कई अन्य आकर्षक पुरस्कार जीतें

Rank	No. of Prizes	Prize Amount for Winners ₹	Prize Amount for Sellers ₹	Prize Amount for Sub-Stockist ₹	Draw Method
1st	1	6,00,00,000	30,00,000	10,00,000	One Complete Number of 6 Digit shall be drawn Either from Series A or B, if number falls from unsold tickets, then machine shall be re-operated till the prize is drawn from sold tickets.
2nd	1	50,00,000	5,00,000	2,00,000	One Complete Number of 6 Digit shall be drawn Either from Series A or B.
3rd	1	25,00,000	2,00,000	1,00,000	One Complete Number of 6 Digit shall be drawn Either from Series A or B.
4th	2	10,00,000	1,00,000	50,000	Two Complete Number of 6 Digit Shall be Drawn along with Series. One from A Series and one from B Series.
5th	2	5,00,000	50,000	20,000	Two Complete Number of 6 Digit Shall be Drawn along with Series. One from A Series and one from B Series.
6th	1,000	9,000	900	100	Ten Numbers of 4 Digits shall be drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, common to all series)
7th	1,000	5,000	500	100	Ten Numbers of 4 Digits shall be drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, common to all series)
8th	1,,000	3,000	300	50	Ten Numbers of 4 Digits shall be drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, common to all series)
9th	40,000	1,000	100	10	Four Hundred Numbers of 4 Digits shall be drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, common to all series)

★ Prize Amount for Sellers & Sub-Stockists above ₹ 10,000 should be claimed from Government only

* TDS 2% UNDER SECTION 393(3) IT ACT 2025 SHALL BE DEDUCTED ON SELLERS PRIZE AMOUNT W.E.F. 01.04.2026

Issued by : Directorate of Small Savings, Banking and Lotteries, Punjab

₹11 CRORES WINNER — PUNJAB STATE DEAR DIWALI BUMPER 2025 — AMIT SEHARA, Draw Date : 31.10.2025, Ticket No. A 438586

₹10 CRORES WINNER — PUNJAB STATE DEAR LOHRI MAKAR SANKRANTI BUMPER 2025 — HARBHINDER SINGH, Draw Date : 18.01.2025, Ticket No. B-566370

₹7 CRORES WINNER — PUNJAB STATE DEAR RAKHI BUMPER 2025 — KRISHNA GOPAL, Draw Date : 16.08.2025, Ticket No. B 673475

₹6 CRORES WINNER — PUNJAB STATE DEAR BAISAKHI BUMPER 2025 — TARSEM LAL, Draw Date : 19.04.2025, Ticket No. B 635931

पूछताछ के लिए, कॉल करें (टोल फ्री) : 1800 103 6711 (पश्चिम बंगाल)

LIVE STREAM http://www.punjabiloteries.com/livedraw

स्वत्वाधिकारी एल.एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक ममता वाजपेयी द्वारा 4,केनाल वेस्ट रोड, कोलकाता -15 से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रेरक संपादकः राजेन्द्र नारायण वाजपेयी । **संपादक : रितेश वाजपेयी।**
Phone: 2236-1572,4800 9234, E-mail-bharatmitral@gmail.com, Fax No.-033-3315-1533, **हवाई शुल्कः** अगरतला 6 रुपये,गुवाहाटी 5 रुपये, पोर्टब्लेयर 8 रुपये। प्रकाशन से उत्पन्न सभी विवाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन